RNI NO. CHHHIN/17604 TC

लाईफ वर्सिटी

LIFE CAMPUS
Learning For Life, Life Long Learning

लाइफ वर्सिटी SCG News

वर्ष : 1 | वर्ष : 01 | 9 जून से 15 जून 2023 | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 5 रू.

राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के दौरान रायगढ़ राममयगढ़ हो गया

प्रभु श्रीराम हमारे दिलों में बसे हैं: बघेल

- महोत्सव को लेकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुए दो विश्व कीर्तिमान
- अरण्यकाण्ड पर सबसे ज्यादा समय तक मंचन का वर्ल्ड रिकार्ड
- तीन दिनों तक 756 मिनट तक 17 दलों के 375 कलाकरों ने किया मंचन
- तीन दिनों तक 10 हजार लोगों ने किया हनुमान चालीसा का किया पाठ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ के रामलीला मैदान में तीन दिवसीय 'राष्ट्रीय रामायण महोत्सव' को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम हमारे दिलों में हैं, हमारे जीवन में हैं। राम नाम का रस ही ऐसा है, जितना सुनिएगा, जितना मनन करिएगा, राम रस की प्यास उतनी बढ़ती जाती है। हमारे राम कौशल्या के राम, वनवासी राम, शबरी के राम, हमारे भांचा राम और हम सबके राम हैं। तीन दिनों तक चले इस महोत्सव में रायगढ़ राममयगढ़ हो गया। इस महोत्सव में नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। तीन दिनों तक पंडाल खचाखच भरा रहा। बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्यों से भी इस महोत्सव में शामिल होने के लिए मेहमान आए। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिससे भी मिले सभी दोहे और चौपाई गुनगुनाते मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में किया गया था, लेकिन कंबोडिया, इंडोनेशिया के रामायण दलों के आने से इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया। उन्होंने जूरी मेम्बरों के विचारों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कहा-हमने देश के विभिन्न हिस्सों में केवल भगवान श्रीराम के बाल्य-काल, रामलीला जैसे अध्यायों का मंचन देखा है। यह पहली बार है कि भगवान राम के अरण्यकाण्ड का मंचन देखने को मिल रहा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया, जो सफल रहा। इस आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई।

प्रदेश की सभी नदियों के संरक्षण के लिए अलग से बनेगा प्राधिकरण

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल समापन समारोह में कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ वनों से अच्छादित है। भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के दौरान इन्हीं जंगलों, नदियों और पहाड़ों के बीच से वन गमन किया। भगवान राम छत्तीसगढ़ के वनों, नदियों, पर्वतों को पार करते हुए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ वनाच्छादित प्रदेश है, जहां कल-कल बहती नदियां हैं, जिनके किनारे हमारी संस्कृति बसती है। हमने अपनी नदियों और प्रकृति को बचाने का संकल्प लिया है। इन्द्रावती और अरपा नदी के संरक्षण के लिए प्राधिकरण गठित किए गए हैं। महानदी, शिवनाथ नदियों के साथ आज केलो की महाआरती की गई। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, इसको बचाएं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी नदियों के संरक्षण के लिए अलग से प्राधिकरण गठित किया जाएगा।

ओड़िशा के रेल हादसे में जान गवाने वालों को दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लाभ-हानि, जीवन-मरण, यश-अपयश भगवान के हाथ में होता है, मनुष्य के नहीं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, भगवान उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, उन्हें अपने चरणों में श्री स्थान दें।

हवन पूजा, सेंगोल की स्थापना और फिर नए संसद भवन का उद्घाटन

देश को नए संसद भवन की जरूरत थी: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन समय की मांग थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा सीटों में इजाफा होगा।

इसके बाद उन्होंने भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों को सम्मानित किया। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और हवन और पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने संसद भवन में सेंगोल स्थापित कर 20 पंडितों से आशीर्वाद लिया।

नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन-जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी।

नए संसद भवन के उद्घाटन के दूसरे चरण में मोदी-मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने नई संसद में प्रवेश किया।

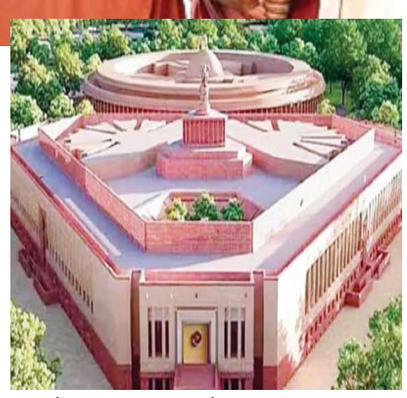

इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने अपना भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपना संबोधन दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संसद भवन ने करीब 30 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया है।

विपक्ष ने साधा निशाना

वहीं, विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। विपक्ष की मौजूदगी के बिना नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता।

राजद के ट्वीट पर हुआ विवाद

राजद ने नए संसद भवन की ताबूत के साथ तस्वीर ट्वीट की, जिससे विवाद पैदा हो गया है। भाजपा ने कहा कि 2024 में जनता राजद को इसी ताबूत में गाड़ देगी।

पंडित नेहरू को सबसे पहले सौंपा गया सेंगोल

सेंगोल को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तातंरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू को सौंपा गया था। नए भवन के इस उद्घाटन मौके पर संसद के दोनों ही सदनों के सदस्यों के साथ ही देश की प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है।

धोती-कुर्ता पहने नजर आए पीएम मोदी

पीएम मोदी नएसंसद के उद्घाटन मौके पर धोती-कुर्ता पहने हुए नजर आए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी को नए संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की।

होलेस्टिक आंकोलॉजी विभाग द्वारा कराया गया विशेष प्रकार की मेडिटेशन

विश्व तम्बाखू निषेद्ध दिवस पर संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल में कार्यक्रम

रायपुर। विश्व तम्बाखू निषेद्ध दिवस पर छग के जाने माने कैंसर हॉस्पीटल संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल एवँ पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन के द्वारा संचालित होलिस्टिक आंकोलॉजी विभाग ने भर्ती मरीजों को राग,रंग और नाद पर आधारित विशेष प्रकार की मेडिटेशन कराया। कैंसर के रोकथाम के लिए नित नए अनुसंधान को बढ़ावा देने और नए उपकरणों का लाभ मरीजो को पहचाने को सदैव तत्पर संजीवनी सीबीसीसी कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉ यूसुफ मेमन एवँ मॉडर्न साइंस को वैदिक विज्ञान के साथ इंटीग्रेट कर हेल्थ और वेलनेस को एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति देने वाले डॉ अनिल गुप्ता ने मिलकर कैंसर के ईलाज एवँ रोकथाम में एक अनूठी पहल की शुरुआत की है।

होलिस्टिक का अर्थ होता है सम्पूर्ण।वैदिक विज्ञान के अनुसार हम पाँच शरीर से मिलकर बने होते है जिसे कोष कहा गया है लेकिन हमें दृश्य एक ही शरीर हकता है।अत: प्राय: इलाज में अन्य शरीर छूट जाए करते है ।किसी भी बिमारी से ग्रसित मरीज का सबसे ज्यादा प्रभावित एक हिस्सा है मन । इसी मन के चलते व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते है और उनमें प्रवाहित होने वाली लाईफ फोर्स एनर्जी गड़बड़ हो जाना रोग का कारक होता है।

हम सभी ने पढ़ा है कि प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवँ क्रियात्मक इकाई को कोशिका या ष्द्यद्य कहते है। अर्थात हम जो भी क्रिया करते है उसका सीधा असर कोशिकाओं में पड़ता है । अर्थात हमारी भावनाओ का असर कोशिकाओं में पड़ता है। एनर्जेटिक होलेस्टिक आंकोलॉजी में हम न्यूरोबीक स्पॉ और न्यूरोबीक एक्सरसाइज के द्वारा मरीज के माइंड और इमोशन पर कार्य किया जाता है। जिसमे राग,रंग और नाद का समावेश कर शरीर में लाइफ फोर्स एनर्जी के प्रवाह का संतुलन बनाया जाता है । इस प्रक्रिया के निरंतर एवँ उचित ढंग से करने से मरीज में रिग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है जो मरीज को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करती है।

पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन की सलाहकार चिकित्सक डॉ स्मृति सिंह,योग ट्रेनर नागेन्द्र साहू और भुनेश्वरी ने मरीजो को मुद्रा लगाना और ध्यान करने का तरीका बताया।पूरे कार्यक्रम में संजीवनी सीबीसीसी के ।क्र अदिति शर्मा और नर्सिंग स्टॉफ का भरपूर सहयोग मिला।अदितिजी ने पूरे समय रुककर इस विधा को समझा और आगे और भी बेहतर ढंग से करने का आश्वासन दिया।

51 रैलियां, 4000 टिफिन मीटिंग

लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में जुटे

मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने के लिए 51 बड़ी रैलियों और 4000 टिफिन मीटिंग आयोजित करने की योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसमें लगभग 15 लाख पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे।

इस अभियान के दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा पवित्र स्थानों की यात्रा भी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह 10 जून को महाराष्ट्र में सिखों के पवित्र स्थान नांदेड़ जाएंगे। यहां वह गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा उसी दिन तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर जाएंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे।

जेपी नड्डा 11-13 जून तक अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में भी तीन दिन बिताएंगे। कुल्लू, कांगड़ा में बज्रेश्वरी देवी मंदिर और पठानकोट में बजुराह जाएंगे।

बीजेपी का लक्ष्य 4000 टिफिन मीटिंग के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने का है ।

प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 31 मई को अजमेर में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किया था।

भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा 14 जून को पंजाब के होशियारपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी 2022 में आम आदमी पार्टी (आप) से विधानसभा चुनाव हारने के बाद पंजाब में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है। पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन पर भी चर्चा जारी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद अकाली दल और भाजपा के बीच फिर से गठबंधन हो सकता है।

भगवा पार्टी ने टिफिन मीटिंग्स शुरू कर दी है। यह तीन घंटे चलती है। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी मोदी सरकार की उपलब्धियों पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद भोजन साझा करेंगे। जेपी नड्डा पहले ही नोएडा में इसकी शुरुआत कर चुके हैं।

बीजेपी का लक्ष्य 4000 टिफिन मीटिंग के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने का है। महीने भर चलने वाला महासंपर्क अभियान 30 जून को समाप्त हो रहा है। बीजेपी इस दौरान राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी उठा रही है। भगवा खेमे के वरिष्ठ नेता देश भर में युद्ध नायकों से भी मिलेंगे। जेपी नड्डा ने जनरल (रिटायर्ड) दलबीर सिंह सुहाग से मुलाकात की थी। उनके कार्यकाल में उरी और म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एएस लांबा और एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) डेन्ज़िल कीलोर से भी मुलाकात की थी

क्या कमजोर रहेगा मॉनसून? अल-नीनो ने बढ़ाई टेंशन

नई दिल्ली। मॉनसून के साथ ही खबर यह है कि अल-नीनो भी सक्रिय है और यह पूरे मॉनसून सीजन के दौरान बना रह सकता है। इससे मॉनसून प्रभावित हो सकता है और इसके चलते बारिश में कमी आ सकती है। यह चिंता की बात है।

मॉनसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है और उम्मीद की जा रही है कि महीने के अंत तक देश के ज्यादातर हिस्सों में यह सक्रिय हो जाएगा। देश में मॉनसून की गतिविधि जून के पहले सप्ताह में शुरू होकर 15 जुलाई तक रहती है और इस दौरान लगभग सभी राज्यों में बारिश हो जाती है। लेकिन इस बीच एक नई टेंशन पैदा होती दिख रही है। दरअसल मॉनसून के साथ ही खबर यह है कि अल-नीनो भी सक्रिय है और यह पूरे मॉनसून सीजन के दौरान बना रह सकता है। इससे मॉनसून प्रभावित हो सकता है और बारिश में कमी आ सकती है।

अमेरिकी मौसम एजेंसियों ने बताया कि अल-नीनो की स्थिति बन चुकी है और यह सर्दियों तक बना रह सकता है। प्रशांत महासागर के जल के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म होने से अल-नीनो की स्थिति पैदा होती है। इससे अकसर मॉनसून प्रभावित होता है और बारिश में कमी आती है। हालांकि हर बार अल-नीनो के असर से ऐसा नहीं होता है। कई बार अल-नीनो के असर के बाद भी सामान्य या उससे थोड़ी ही कम बारिश हो जाती है। अल-नीनो अमूमन हर 4 साल के अंतराल पर सक्रिय होता है। इससे पहले 2018-19 में अल-नीनो सक्रिय हुआ था।

गुरुवार को अमेरिकी मौसम एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रशांत महासागर में अल-नीनो की स्थिति बनने लगी है। महासागर के जल का तापमान औसत से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। बता दें कि बीते दोनों महीनों में दुनिया भर की मौसम एजेंसियों ने यह अनुमान जताया है कि इस मॉनसून सीजन के दौरान अल-नीनो सक्रिय हो सकता है। यह भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है।

सब्सिडी घोटाला

हेराफेरी से बिका हर दूसरा दोपहिया वाहन, सरकार ने रकम में की कटौती

महंगी हो जाएंगी गाड़ियां

नई दिल्ली। सब्सिडी लेने के नाम पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों ने बड़ा हेर-फेर किया है। हर दूसरा वाहन इस हेराफेरी के जरिये बिका है। इसे देखते हुए सरकार ने गलत तरीके से ली गई कंपनियों की सब्सिडी राशि में कटौती कर दी है। इससे एक जून से कई कंपनियों के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 25-40 हजार रुपये तक महंगे हो जाएंगे।

हेरा-फेरी की जांच से जुड़े लोगों का दावा है कि स्थानीयकरण के मानकों को पूरा करने के नाम पर कंपनियों ने सरकार से सब्सिडी हासिल कर ली है। हकीकत यह है कि कंपनियों ने विदेश से कलपुर्जे मंगाकर वाहनों का निर्माण किया और सरकार से सब्सिडी ले ली। इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर और ऑन बोर्ड चार्जर्स को विदेश से मंगाकर दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया है।

सरकार ने रोकी 1400 करोड़ की सब्सिडी

सरकार ने इस खुलासे के बाद 1400 करोड़ रुपये की सब्सिडी रोक दी है। फेम सब्सिडी के तहत हेरा-फेरी को लेकर हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और ओला, ग्रीव्स कॉटन के नाम सामने आए हैं। आरोप हैं कि इन कंपनियों ने फेम-2 स्कीम के तहत सब्सिडी पाने के लिए विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में किया और उन्हें घरेलू बताया है।

केंद्र सरकार ने ओकिनावा ऑटोटेक पर 116 करोड़ का रिकवरी नोटिस जारी किया है। हीरो इलेक्ट्रिक को 133 करोड़ रुपये वापस करने को कहा गया है। ओला इलेक्ट्रिक 130 करोड़ रुपये लौटाने का तैयार हो गई है।

फेम-2 के तहत कीमत 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

केंद्र सरकार फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक (फेम) योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देती है। सब्सिडी लेने लिए कंपनियों को दो पहिया वाहन की कीमत अधिकतम 1.5 लाख रुपये रखना होता है। वाहन में लिथियम ऑयन बैटरी का इस्तेमाल भी जरुरी है। वहीं 50 फीसदी से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए।

आयकर विभाग के नोटिस का नहीं दिया जवाब तो बढ़ेगी परेशानी

आयकरदाताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'जांच' के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऐसे आयकरदाताओं जिन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन मामलों की जांच भी करेगा जहां किसी लॉ इंफोर्समेंट एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा टैक्स चोरी से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

पिछले सप्ताह चला था अभियान

गौरतलब है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश पर आयकर

विभाग ने इस महीने 16 तारीख से देशभर में टैक्स चोरी, जीएसटी चोरी, फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे मामलों को रोकने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान जिन आयकरदाताओं के दस्तावेज संदेहास्पद मिले हैं उन्हें सीबीडीटी ने नोटिस भेजा था। वहीं, इंडीविजुअल करदाताओं को भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन जिन लोगों ने अब तक जवाब नहीं दिया है उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

ये है नई गाइडलाइन

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कर अधिकारियों को आय में गड़बड़ियों के बारे में करदाताओं को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा। इसके बाद आयकरदाताओं को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे। बता दें, नए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा।

आपको बता दें, आयकर अधिनियम की धारा 142(1) इनकम टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है। जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया हो उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है। ऐसे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इंटीग्रेटेड लिस्ट जारी करता है, जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रियायत या कटौती की मांग करता है।

इसके अलावा कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत आयकरदाताओं को एनएएफएसी के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा।

आईटीआर की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए फॉर्म 1 और 4 जारी

नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन ई फाइलिंग के लिए आईटीआर -1 और आईटीआर -4 फॉर्म जारी कर दिया है। इसका फायदा उन टैक्सपेयर्स को मिलेगा, जो ऑनलाइन टैक्स भरते हैं। ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें आईटीआर -1 और आईटीआर - 4 के जरिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिये वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक और चार ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है। विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अन्य आयकर रिटर्न/फॉर्म के लिये सुविधाएं जल्द शुरू की जाएगी।

विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिये ऑनलाइन आईटीआर एक और चार भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आईटीआर एक वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं। वहीं आईटआर दो कंपनियां और पेशेवर भरते हैं। यह उन इकाइयों के लिये है जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

आपको बता दें कि ई फाइलिंग एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म के मुकाबले आसान प्रक्रिया है।

सेवाओं के लिए ग्राहक को मोबाइल नंबर देने के लिए नहीं कहें खुदरा विक्रेता

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने परामर्श जारी कर खुदरा विक्रेताओं को कुछ सेवाएं देने के लिए ग्राहकों के व्यक्तिगत संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के मिलने के बाद यह परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर वे अपना संपर्क नंबर साझा करने से इनकार करते हैं तो वे उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।

सचिव ने संवाददाताओं से कहा, ''विक्रेताओं का कहना है कि जब तक व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक वे बिल नहीं बना सकते हैं। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है और जानकारी एकत्र करने के पीछे कोई तर्क नहीं है।'' उन्होंने कहा कि गोपनीयता की चिंता भी है। इसलिए, उपभोक्ताओं के हित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए खुदरा उद्योग और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) एवं फिक्की को एक परामर्श जारी किया गया है।

भारत में ग्राहकों के लिए बिल बनवाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, खुदरा विक्रेताओं द्वारा लेन-देन पूरा करने के लिए एक नंबर पर जोर देने से ग्राहकों को एक अजीब स्थिति में डाल दिया जाता है। अधिकांश समय, ग्राहकों को इनमें से कई स्थितियों में इससे बचने का विकल्प नहीं दिया जाता है।

1 जून से सेविंग और करंट अकाउंट में होगा बड़ा बदलाव

पोर्टल जारी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जून से सेविंग और करंट अकाउंट में बड़ा बदलाव होने की बात कही है। इसके लिए बैंक ने 100 दिन 100 कैंपेन की शुरुआत की है। इसमें सभी बैंकों को 100 दिन के अंदर ही डिपॉजिट मनी को सेटल करना होगा। सभी बैंकों को यह कार्य 1 जून 2023 से शुरू करने के लिए कहा गया है।

आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक सेविंग और करंट अकाउंट में बची हुई वह राशि जो 10 वर्षों से ऑपरेट नहीं की गई हो या फिर मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के अंदर किसी ने दावा नहीं किया हो। तब उस स्थिति में डिपॉजिट मनी को अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया जाएगा। आरबीआई के तहत बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रांसफर किया जाता है।

इसी साल अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि मौजूदा अनक्लेम्ड डिपॉजिट राशि का पता लगाकर उसके सही मालिकों को वापस दे दी जाएगी। यह फैसला जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया। इसी कारण से आरबीआई ने कई बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया है।

सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर जून तक नहीं लगेगा आयात शुल्क

नई दिल्ली। भारत सरकार ने जून तक कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल से आयात शुल्क हटाने का फैसला लिया है। सरकार ने आयात शुल्क में देने वाली छूट को लेकर स्पष्ट किया है कि 31 मार्च से पहले भेजे जाने वाले सोया तेल और सूरजमुखी तेल के आयात को मुफ्त रखा जाएगा, क्योंकि आयात नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी, जिससे सैकड़ों हजारों कार्गो बंदरगाहों पर फंस गए थे। गौरतलब है, इस साल की शुरुआत में वनस्पति तेलों के दुनिया के सबसे बड़े आयातक ने 1 अप्रेल से चालू वित्त वर्ष के लिए 2 मिलियन टन कच्चे

गिर सकता है पाम तेल का इम्पोर्ट

सूरजमुखी तेल और सोया तेल के आयात शुल्क में देने वाली छूट को समाप्त कर दिया था। डीलरों का कहना था कि इस कदम से भारतीय बंदरगाहों पर करीब 90 हजार टन माल से लदे कार्गो फंस गए थे, जिन्हें 31 मार्च से पहले लोड किया गया था।

वनस्पति तेल ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी फर्म सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बाजोरिया ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से कुछ कार्गो बंदरगाहों पर अटके हुए थे। अब सरकार के नए आदेश के बाद ये देश में प्रवेश कर सकते हैं। बता दें, भारत मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका से सोया तेल और रूस व यूक्रेन से सूरजमुखी का आयात करता है।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने का कहना है कि सरकारी अधिसूचना से आयातकों को राहत मिलेगी। वहीं आयात स्थानीय तिलहन की कीमतों को कम करेगा। साथ ही किसानों की आय में भी कमी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि मई में भारत का पाम तेल आयात भी गिर सकता है क्योंकि सोया और सूरजमुखी तेल की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

छोटी योजनाओं में 10 लाख या अधिक के निवेश पर अब देना होगा कमाई का सबूत

नई दिल्ली। अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का निवेश करने पर आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे को रोकने के लिए डाक विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। डाक विभाग का कहना है कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले कुछ क्लास के निवेशकों को आय प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। अगर निवेशक ऐसा नहीं करते हैं तो वे 10 लाख या उससे अधिक पैसे का निवेश नहीं कर पाएंगे।

डाक विभाग की ओर से ग्राहक को जानो (केवाईसी) के संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार, अब सभी योजनाओं में निवेश के लिए पैन व आधार देना होगा। भारत के बाहर रहने वाले राजनीतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों (पीईपी) से संबंधित खाते उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत आएंगे।

ये कागजात भी मान्य

बैंक या डाकघर खाते का विवरण, जिसमें पैसे की पूरी जानकारी हो। पिछले तीन साल में से किसी एक साल के आईटी रिटर्न का विवरण।

निवेशकों को तीन श्रेणियों में बांटा

डाकघर की सभी योजनाओं में कुल निवेश 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं तो कम जोखिम वाला निवेशक।

50 हजार रुपए से ज्यादा, पर 10 लाख रुपए से कम रकम वाले निवेशक मध्यम जोखिम श्रेणी में रकम

10 लाख या इससे ज्यादा है, तो फिर निवेशक उच्च जोखिम श्रेणी में इनके ऊपर कड़े प्रावधान लागू होंगे।

जी-7 देशों ने रूसी हीरे पर लगाया प्रतिबंध, भारत में 10 लाख नौकरियों पर संकट

भारत में 10 लाख लोगों के रोजगार पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि जी-7 देशों ने रूस में खनन किए गए हीरों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत में हीरों का कारोबार दुनिया में उपलब्ध 10 में से 9 हीरों को काटने और पॉलिश करने का काम करता है और अलरोसा से रूसी हीरे का इम्पोर्ट करता है, जो वैश्विक कच्चे हीरे के उत्पादन का 30% है। जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के चेयरमैन विपुल शाह का कहना है कि अगर यह प्रतिबंध जारी रहता है तो भारत में 10 लाख कर्मचारियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा।

जी 7 देश यूक्रेन में अपने युद्ध के प्रयासों को और बाधित करने की कोशिश करने के लिए रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस प्रक्रिया में सूरत में हीरा श्रमिकों को रूस से कच्चे हीरे की अनुपलब्धता के कारण ग्लोबल आर्थिक मंदी के बीच मांग में गिरावट और बड़े पैमाने पर चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। कच्चे हीरे की सप्लाई कम होने के बाद भी हीरा इंडस्ट्री स्थिति को संभालने में सक्षम हो रहा है लेकिन मांग बढ़ने पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पता लगाने की क्षमता चुनौती

विपुल शाह ने कहा कि हीरे के एक विशेष टुकड़े की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी पहचान करने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है। जी-7 मूल की पहचान करने और वर्ल्ड मार्केट में रूसी हीरे के मूवमेंट को कम करने के लिए पता लगाने की तकनीक को इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस की ओर से हीरे के एक्सपोर्ट से निकाले जाने वाले राजस्व को कम करने के लिए रूस में खनन, संसाधित या उत्पादित हीरों के कारोबार और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा।

जीजेईपीसी के शाह ने कहा कि मौजूदा समय में हीरों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए ऐसी कोई तकनीक नहीं है। अब हमारे पास किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन है। किम्बर्ले प्रोसेस एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे 2003 में कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के प्रवाह को रोकने के के लिए स्थापित किया गया था। इस व्यवस्था का मूल किम्बर्ले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) है जिसके तहत राज्य कच्चे हीरे के शिपमेंट पर सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं।

लीव एनकैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर की गई 25 लाख

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर लीव एनकैशमेंट के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। पहले यह सीमा तीन लाख रुपये की थी। इसे 2002 में तय किया गया था, जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था। नई ?सीमा एक अप्रैल, 2023 से लागू हो गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को कहा, धारा 10(10एए)(2) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी। यह भुगतान एक गैर-सरकारी कर्मचारी को एक से ज्यादा नियोक्ता से मिलता है। फरवरी, 2023 में पेश इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या लीव एनकैशमेंट पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया था।

वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों को अधिसूचित किया है, जहां से गैर सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप में अनिवासी निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। सूची में सिंगापुर, नीदरलैंड व मॉरीशस जैसे देशों के निवेश शामिल नहीं हैं। अधिसूचना एक अप्रैल से लागू है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में एंजेल टैक्स नेट के तहत डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को छोड़कर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशी निवेश के तहत लाया था।

2000 का नोट वापस लेने से अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा: पनगड़िया

नई दिल्ली। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि 2000 का नोट वापस मंगाने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे वापस हुए नोटों के स्थान पर उसी कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोट जारी कर दिए जाएंगे।

पनगड़िया ने कहा कि इस कदम के पीछे संभावित मकसद अवैध धन की आवाजाही को और मुश्किल बनाना है।

उन्होंने कहा, हम इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखेंगे। 2,000 के नोट की कितनी भी राशि को बराबर कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोटों से बदल दिया जाएगा या जमा कर दिया जाएगा। इसलिए धन प्रवाह पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पनगरिया ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट वर्तमान में जनता के हाथों में कुल नकदी का केवल 10.8 प्रतिशत हैं और इसमें से भी ज्यादातर राशि का उपयोग संभवतः अवैध लेनदेन में होता है।

वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शनिवार को कहा कि 2,000 रुपये का नोट वापस लिए जाना 'बहुत बड़ी घटना' नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था या मौद्रिक नीति पर कोउन्होंने कहा कि 2,000 रुपये के नोट को 2016 में विमुद्रीकरण के समय 'आकस्मिक कारणों' से मुद्रा की अस्थायी कमी को दूर करने के लिए लगाया गया था। गर्ग ने कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों में डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि के बाद, 2,000 रुपये का नोट (जो वास्तव में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के स्थान पर लाया गया था) वापस लेने से कुल मुद्रा प्रवाह प्रभावित नहीं होगा और इसलिए मौद्रिक नीति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत की जीडीपी पहली बार 350 लाख करोड़ पार, अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। बीते कैलेंडर ईयर यानी 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पहली बार 3.5 लाख करोड़ डॉलर (350 लाख करोड़) से ऊपर निकल गया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारत अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढने् वाली जी-20 अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन इसके लिए कुछ सुधारों की जरूरत होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में भारतीय जीडीपी 3.18 लाख करोड़ डॉलर यानी 263.50 लाख करोड़ रुपए की थी।

बहरहाल, मूडीज ने एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा कि ब्यूरोक्रेसी विभिन्न लाइसेंस लेने और बिजनेस स्थापित करने की प्रक्रिया धीमी कर सकती है। साथ ही प्रोजेक्ट की अवधि और लागत बढ़ा सकती है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि निर्णय लेने में लेटलतीफी की वजह से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की रफ्तार कम हो सकती है। खास तौर पर तब जब एशिया-प्रशांत की अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं,

मसलन इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ भारत तगड़ी प्रतिस्पर्धा में है।

मकान, सीमेंट और कार की डिमांड बड़ाएगा

तेज शहरीकरण

मूडीज के मुताबिक भारत में बड़ी और पढ़ी-लिखी वर्कफोर्स है। ऐसे में छोटे परिवार बढ़ेंगे। साथ ही तेज शहरीकरण से घर, सीमेंट और कार की डिमांड बढ़ेगी। मूडीज के मुताबिक भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च स्टील और सीमेंट सेक्टर्स के लिए मददगार होगा, जबकि नेट-जीरो एमिशन हासिल करने की चाहत अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देगी। मूडीज ने ये भी कहा कि इन सेक्टरों में भारत की क्षमता 2030 तक चीन से कम रहेगी। जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है।

सकारात्मक जीवनशैली तनाव रहित जीवन

जीवन में सबसे मुश्किल काम है सरल, संतुलित बने रहना, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर कुछ बातों को आप अपनी रोजाना और जीवन का हिस्सा बनाकर अपनी आदत में शामिल कर लेंगे तो जीवन ना सिर्फ आसान लगेगी, बल्कि बेहतर भी बनेगी।

शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके साथ कोई समस्या नहीं हो... समस्या से घिरे रहने से सिर्फ तनाव ही होगा। इसलिए समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान दें। अक्सर लोग समस्याओं के घेरे में घिरे रहते हैं जिसके चलते वह घर का महौल भी वैसा ही बना लेते है। इस सब का सीधा प्रभाव जीवन पर और घर के माहौल पर पड़ता है। आप तो परेशान होते ही है साथ आपसे जुड़े व्यक्ति भी परेशान होने लगते हैं इसलिए इस बात को स्वीकार करें कि जीवन है तो समस्याएं रहेंगी इससे कैसे निपटना इस ओर विचार करें।

घर का माहौल

जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाता है घर का माहौल। घर के माहौल को हमेशा खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करें। आजकल परिवार एकल है, और इसका सीधा प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है। घर का हर सदस्य अपने-अपने कामों में उलझा रहता है। एक -दूसरे के साथ समय बिताने का मौका शायद ही किसी को मिलता हो। जब भी इकट्ठे हों एक-दूसरे से प्रेम से बात करें। उनके जीवन से जुड़ी बातें जानने का प्रयास करें। एक-दूसरे के मन को जानें। जरूरी नहीं कि हर समय गंभीर विषयों पर ही परिवार के सदस्यों से चर्चा की जाए सामान्य विषयों पर भी परिवार के साथ चर्चा की जा सकती है।

सक्रिय रहें

खाली दिमाग शैतान का घर ये बात आपने सुनी ही होगी। अतः अपने आप को किसी न किसी काम में उलझाए रखें। यदि आप खाली बैठते हो तो तरह-तरह के अच्छे-बुरे विचार मन में आते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता कि पुरानी बातों को लेकर उसी के बारे में सोचने लगते हैं और यही सब बातें तनाव का कारण बनती है। इसलिए जितना हो सके

सकारात्मक रहें

आज के समय में बड़ा हो या छोटा हर किसी को छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने की आदत सी बन गई। यहां तक कि छोटी उम्र के बच्चे तक माता पिता के डांटने पर गुस्सा हो जाते हैं खाना नहीं खाते हैं तो बड़ों के बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन परिणाम दोनों के एक जैसे ही आते हैं। जीवन को बेहतर तरीके से जीने का एक ही उपाय है... वह है बेहतर नजरिया।

आप जीवन के प्रति जितने सकारात्मक होंगे जीवन उतना ही अच्छा और सकारात्मक नजर आने लगेगा। इसलिए जीवन के प्रति अपने नजरिए को बदले फिर देखिए कि जीवन खुशहाल नजर आने लगेगा। कोई बात को मन से लगाकर न रखें। मन में एक ही बात बैठाकर उसी नजरिए को सही ना मानें। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक और प्रगतिशील रखें। नकारात्मक सोचने वालों के साथ ज्यादा बातचीत ना करें। जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी लेने का जज्बा पैदा करें। हमेशा जिंदगी से शिकायत करते रहने से हालात बदलेंगे नहीं, बल्कि आपके दुख ही बढ़ेंगे। ऐसे में जिन्दगी में जो अच्छे पल आपके पास हैं, वो भी आप से छिन जाएंगे। बेहतर होगा, उन्हें एंजॉय करें।

वैदिक साहित्य में समाया सृष्टि का ज्ञान-विज्ञान

वैदिककाल में पर्यावरण के परिष्कार के लिए यज्ञ-हवन संपन्न किए जाते थे।

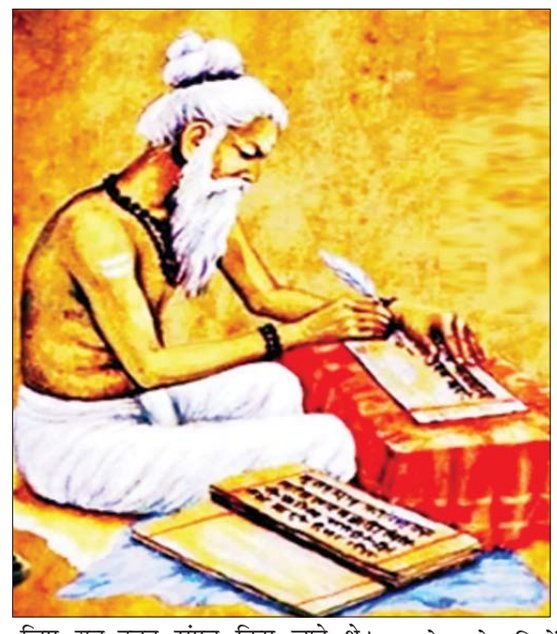

समूची सृष्टि पंचमहाभूत अर्थात अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बनी है। यही पांच तत्व मिलकर समूचे विश्व ब्रह्मांड के जड़, चेतन और जीवों का निर्माण और पोषण करते हैं। वैदिक मनीषियों का प्रतिपादन है कि इन पंचमहाभूतों का संतुलन ही जीवनचक्र को नियंत्रित करता है और इसमें गतिरोध आते ही जीवन संकट में पड़ जाता है।

इसीलिए वैदिक ऋषियों ने इन पंचतत्वों को शुद्ध एवं संरक्षित रखने हेतु अनेक नियम-उपनियम बनाए थे। ऋग्वेद में अग्नि के रूप-गुण और रूपांतर, यजुर्वेद में जल तथा वायुतत्व के गुणों, कार्य और विभिन्न रूपों एवं अथर्ववेद में पृथ्वीतत्व के गुणों की अद्भुत व्याख्या की गई है। वैदिककाल में इन प्राकृतिक शक्तियों को देवस्वरूप माना जाता था। इसीलिए उस युग में समस्त सृष्टि में सुख-शांति व समृद्धि का वातावरण था।

ऋग्वेद की ऋचा कहती है-हे वायु! अपनी औषधि ले आओ और यहां से सब दोष दूर करो, क्योंकि तुम ही सभी औषधियों से भरपूर हो। ऋग्वेद का एक अन्य मंत्र जल की शुद्धता का वर्णन करते हुए कहता है, आओ सभी मिल कर प्रवाहित जल के प्रशंसा के गीत गाएं जो हजारों धाराओं से स्फटिक की तरह बहकर आंखों को आनंद देता है। उपनिषद्कारों ने भी ऊर्जा के अपरिमित स्रोत सूर्य को जगत की आत्मा कहकर उसकी अभ्यर्थना की है, सूर्य को प्राण की संज्ञा दी है।

यज्ञों के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध करना भी वेदों का विषय रहा है। वैदिककाल में पर्यावरण के परिष्कार के लिए यज्ञ-हवन संपन्न किए जाते थे। सामवेद में जीवन की मंगलकामना और प्रकृति की अविरल उपासना के भाव वर्णित हैं। इसमें वनस्पतियों और पशुजगत तथा औषधि विज्ञान के सुंदर मंत्रों के उद्धरण हैं। सामवेद कहता है झ हे इंद्र, सूर्य रश्मियों और वायु से हमारे लिए औषधि की उत्पत्ति करो। हे सोम, आपने ही औषधियों, जलों और पशुओं को उत्पन्न किया है।

अथर्ववेद में भी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संबंधी चिंतन का गौरवगान हुआ है। पृथ्वी सूक्त में अथर्वण ऋषि धरा की महानता, उदारता, सर्वव्यापकता आदि अनंत गुणों पर विस्मित हो कह उठते हैं, हे माता! आपके लिए ईश्वर ने शीत, वर्षा तथा वसंत ऋतुएं बनाई हैं। दिन-रात के चक्र स्थापित किए हैं। इस कृपा के लिए हम ईश्वर के आभारी हैं।

वे खनन से पूर्व धरती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, जीविकोपार्जन के लिए हम ऐसा करने को बाध्य हैं, किन्तु हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह तुम्हें पुनः हरा-भरा कर दे। हम भूमि के जिस स्थान पर खनन करें, वहां शीघ्र ही हरियाली छा जाए। आपसे प्रार्थना है कि ऐसी सद्धबुद्धि दें जिससे हम आपके हृदय स्थल को न तो आहत करें, और न ही आपको दुःख पहुंचाएं। व्यक्ति स्वस्थ, सुखी दीर्घायु रहे, नीति पर चले और पशु वनस्पति एवं जगत् के साथ साहचर्य रखे, यही वैदिक साहित्य की विशेषता है।

वैदिक कर्मकांडों की अनेक विधाओं में भी पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा का दायित्व निभाया गया है। अरण्यों में रहकर पर्यावरण के प्रति विशेष जागरूक रहने वाले ऋषियों ने आरण्यक साहित्य का सृजन कर विश्व में पर्यावरण के महत्त्व को रेखांकित किया है।आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों के बीच की कड़ी हैं। 'अरण्ये भवमेति आरण्यकम्' कहकर आरण्यक का अर्थ स्पष्ट किया गया है। बृहदारण्यक भी 'अरण्येनूत्यमानत्वात अरण्यकम के रूप में इसका समर्थन करता है। इसका विषय प्राणविद्या है।

अंतरिक्ष और वायु से प्राण का संबंध अन्योन्याश्रित है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में भी वायु और अंतरिक्ष का विशेष योगदान रहता है। सृष्टि के सभी तत्वों में इन दोनों का समावेश है। इन्हीं गुणों के कारण सृष्टि के सभी तत्वों को प्राणशक्ति मिलती है जिससे विकास की गति अग्रसर होती है।

दुःख का विषय है कि आधुनिकता की आंधी ने पर्यावरण संरक्षण की इस वैदिक परंपरा को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोहन और शोषण, वैभव एवं विलास की रीति नीति ने पर्यावरण को घोर संकट में डाल दिया है। समस्या के सार्थक निदान के लिए जरूरी है कि हम अपनी विरासत को संभालें। पर्यावरण संरक्षण की टूट-बिखर रही कडियों को पुनः जोड़े। हममें से प्रत्येक मन-वाणी-कर्म से इस सत्य का वेदकालीन महर्षियों के स्वर-में-स्वर मिलाकर सस्वर उद्घोष करें- ? द्यौ शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः। जब हम अपने आचरण व्यवहार से माता प्रकृति के कोप को शांत करेंगे, तभी हमारा अपना जीवन भी शांत और सुखी होगा।

उपनिषदों में विशद् वर्णन

उपनिषदों में जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष का विशद् वर्णन हुआ है। इनके अनुसार पदार्थ की उत्पत्ति एवं जीव-जगत् की सृष्टि अग्नि, जल और पृथ्वी के विनियोग से हुई है। पृथ्वी का रस जल है और जल का रस औषध है। रामायण व महाभारतकालीन मनीषियों ने भी पर्यावरण की गौरव गरिमा को महिमा मंडित किया है।

विभिन्न साहित्यिक उद्धरण बताते हैं कि उन दिनों पर्यावरण अत्यंत समृद्ध था। रामायण कालीन ग्रंथों में प्रकृति को सजीव व निर्जीव दोनों ही तत्वों से चेतना संपन्न बताया गया है। उन दिनों वृक्षों की पूजा का प्रचुर प्रचलन था। वृक्षों को काटना महापाप समझा जाता था। वहीं महाभारत काल में भगवान् कृष्ण ने भगवद्गीता में प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण बताया गया है।

श्रीकृष्ण कहते हैं , प्रकृति के कण -कण में सृष्टि का रचयिता समाया हुआ है। प्रकृति के समस्त चमत्कारों को परमेश्वर का स्वरूप बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी भूत-प्राणियों को धारण करता हूँ। चंद्रमा बनकर औषधियों का पोषण करता हूं। महाभारतकाल में प्रत्येक तत्व को देवता सदृश स्वीकार कर उनकी अभ्यर्थना की जाती थी। महाभारत के आदिपर्व में वर्णन है कि गाँव में जो जगह पेड़ फूल और फलों से भरपूर हो, वह स्थान हर तरह से अर्चनीय है। पवित्र और शीतल जलाशय तथा जंगल पहाड़ व पर्वतों आदि को प्रकृति व पर्यावरण के अद्भुत प्रसंगों से महाभारत के सभी पर्व भरे पड़े हैं।

होलिस्टिक थैरेपी क्या होती है, क्या वाकई सभी रोगों का करती है नाश

इस थैरेपी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जाती है

होलिस्टिक थैरेपी के जरिए असंतुलित जीवनशैली को सुंतलित जीवनशैली में बदला जाता है. इस थैरेपी में मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जाती है. आइए जानते हैं क्या होती है होलिस्टिक थैरेपी और यह कैसे काम करती है.

आज एक बार फिर होलिस्टिक थैरेपी को महत्व दिया जा रहा है. धार्मिक और पवित्र तरीके से उपचार लेने को ही होलिस्टिक थैरेपी कहा गया है. होलिस्टिक थैरेपी के जरिए असंतुलित जीवनशैली को सुंतलित जीवनशैली में बदला जाता है. इस थैरेपी में मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जाती है. आइए जानते हैं क्या होती है होलिस्टिक थैरेपी और यह कैसे काम करती है.

यह होती है होलिस्टिक थैरेपी

जो भी लोग गोलियां, सिरप लेने और ऑपरेशन की काट-छांट से बचना चाहते हैं, ऐसे लोग होलिस्टिक थैरेपी को अपनाते हैं. अगर किसी के साथ कभी कुछ एमरजेंसी घट गई हो, तो ऐसी स्तिथि में पहले दूसरी चिकित्सा की मदद से उसे ठीक किया जाता है. इसके बाद धीरे-धीरे होलिस्टिक थैरेपी की जाती है. होलिस्टिक थैरेपी में शरीर के सभी अंगों पर बारिकी से ध्यान दिया जाता है. बता दें कि, होलिस्टिक थैरेपी किसी तरह का इलाज नहीं है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का एक बेहतर तरीका है. इस थैरेपी के दौरान बॉडी के पेन से संबंधित हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है, हर समस्या का हल ढूंढ़ा जाता है, इसलिए उपचार के बाद संपूर्ण शरीर स्वस्थ्य हो जाता है.

मन और शरीर का संगम हैं होलिस्टिक थैरेपी

होलिस्टिक थैरेपी असल में लाइफस्टाइल को बदलने का ही तरीका है. इस थैरेपी में पूरा उपचार मन और शरीर के संगम से होता है. होलिस्टिक थैरेपी में पूरा उपचार होना बेहद ही महत्वपूर्ण है. इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं सहित धार्मिक विश्वास पर ध्यान दिया जाता है.

थेरेपी में नहीं होता दवा उपकरणों का प्रयोग

होलिस्टिक थेरेपी में किसी भी प्रकार की दवाओं या उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. हमारा शरीर जिन पंचतत्वों से बना हैं उन पंचतत्वों के असंतुलन के कारणों को होलिस्टिक थैरेपी में देखा जाता है. इन कारणों में मुख्य रूप से पौष्टिक भोजन का सेवन नहीं करना, नियमित व्यायाम नहीं करना, मानसिक, भावनात्मक

और धार्मिक जरूरतों का पूरा नहीं होना शामिल है. जब भी होलिस्टिक थैरेपी दी जाती है तो मनुष्य के दिमाग, शरीर, भावना और आत्मा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है.

होलिस्टिक थैरेपी देने वाला सबसे पहले व्यक्ति के शरीर का पूरा जायजा लेता है, उससे संबंधित पूरी जानकारी जुटाता है, उसके बाद कोई इलाज बताता है. इसलिए होलिस्टिक हीलर का सही चुनाव करना भी बेहद आवश्यक है. होलिस्टिक हीलर ऐसा होना चाहिए जिस पर आपको पूरा विश्वास हो साथ ही दिए जाने वाले उपचार का उसे पूरा ज्ञान हो.

ये 5 हानिकारक आदतें बढ़ाती हैं आपके पेट का मोटापा, जानें पेट की चर्बी घटाने के उपाय

होलिस्टिक थैरेपी के प्रकार-

- अरोमा थेरेपी
- आयुर्वेदिक इलाज
- प्राकृतिक भोजन
- योग और व्यायाम
- काउंसलिंग
- हर्बल उपचार
- यूनानी चिकित्सा
- एक्युपंक्चर
- नेचुरोपैथी
- एनर्जी हीलिंग
- प्रार्थना साधना
- चाइनीज मेडीसिन
- ऑल्टरनेट मेडीसिन
- कंप्लिमेंटरी मेडीसिन
- इंटीग्रेटिव मेडीसिन
- रेकी
- प्राणिक हीलिंग
- करुणा रेकी
- एक्युप्रेशर
- ध्यान
- विपश्यना
- मालिश
- प्रेक्षा ध्यान
- सिद्धा ध्यान

एक स्वस्थ जीवन शैली में संतुलित आहार का महत्व

एक संतुलित आहार बनाए रखते हुए और शरीर द्वारा आवश्यक सभी पोषक तत्वों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए एक स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त की जा सकती है। एक उचित आहार योजना शरीर के आदर्श वजन को प्राप्त करने और मधुमेह, हृदय और अन्य प्रकार के कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है।

एक स्वस्थ आहार खाना बहुत अच्छा महसूस करना है, अधिक ऊर्जावान होना, अपने स्वास्थ्य में सुधार होना और मनोदशा को प्रोत्साहित करना है। अच्छा पोषण, शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ शरीर का वजन व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक अंग है।

शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से कई स्वास्थ्य समस्याएं प्रबंधित होती है और तनाव, अवसाद और दर्द को कम करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित व्यायाम चयापचय सिंड्रोम, आघात, उच्च रक्तचाप, गठिया और व्याकुलता को रोकने में मदद करता है।

आहार के विकल्पों के चयन के लिए एक विस्तृत विविधता प्रत्येक पाँच खाद्य समूहों में बताए गए मात्रा में से होना चाहिए। प्रत्येक खाद्य समूह के ये खाद्य स्रोत शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख मिक्रो और मैक्रो-पोषक तत्वों की एक समान मात्रा प्रदान करते हैं।

एक संतुलित आहार में आमतौर पर 50 से 60 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 12 से 20 प्रतिशत प्रोटीन और 30 प्रतिशत वसा होता है। सभी अंगों और ऊतकों को एक आदर्श वजन बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों और कैलोरी की सही मात्रा का सेवन करके प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण अच्छे पोषण, शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ शरीर के वजन पर निर्भर करता है।

एक उचित आहार का प्रारूप प्रत्येक विशिष्ट आयु वर्ग के लिए भोजन सामग्री, खाद्य पदार्थों और नाश्ते, दोपहर के भोजन, नाश्ते और रात के खाने के लिए आवश्यक मात्रा का एक पूरा सम्मिश्रण है। आपको अपनी मांसपेशियों और रक्त कोशिकाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो आपके मांसपेशियों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व लाता है।

शारीरिक स्वास्थ्य और सेहत को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम के साथ शरीर को गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट, बिना चर्बी वाला प्रोटीन, आवश्यक वसा और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है।

ये अतिरिक्त वजन बढ़ाने या वजन घटाने को बनाए रखने में प्रभावी होते है लेकिन ज्यादा स्वस्थ जीवनशैली भी बेहतर नींद और मन:स्थिति से जुड़ी हैं। शारीरिक गतिविधि विशेष रूप कर मस्तिष्क से संबंधित कार्यों और परिणामों में सुधार करती है। शारीरिक गतिविधि के साथ अपने आहार में छोटे बदलाव करने से शरीर उचित वजन को प्राप्त करने में अच्छा समय लग सकता है। सही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मिठाई और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले साधारण कार्बोहाइड्रेट पर भरोसा करते हैं।

फल और सब्जियां प्राकृतिक रेशे, विटामिन, खनिज और अन्य यौगिकों के समृद्ध स्रोत हैं जो आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यकता होती है। उनमें कैलोरी और वसा भी कम होती है। असंतृप्त वसा सूजन को कम करने और कैलोरी प्रदान करने में मदद कर सकती है।

शरीर के 7 चक्र जिन्हें जानकर पुरानी बीमारियों का भी हो सकता है इलाज

आपके शरीर के चक्रों से जुड़ीं हुई कई बातों को सुना और पढ़ा होगा लेकिन क्या आप इन चक्रों के बारे में अच्छी तरह जान पाए हैं? असल में हमारे शरीर में सात तरह के चक्र होते हैं, जिनका हमारी हेल्थ से सीधा कनेक्शन है। ये चक्र आत्मा, शरीर और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बैठाने का काम करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे शरीर में ऊर्जा का एक जुड़ाव हो और समान रूप से प्रवाह हो। ये चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सिरे से शुरू होते हैं और आपके सिर के ऊपर तक जाते हैं।

चक्र क्या हैं?

चक्र शब्द का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है पहिया और हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। आपके शरीर में मौजूद सात चक्र ऊर्जा केंद्र हैं और ये भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं। जब ये चक्र कभी भी असंतुलित हो जाते हैं, तो वे आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक चक्र एक शरीर के अंग और उसके कार्यों से जुड़ा हुआ है।

चक्रों का स्थान क्या है?

आपके शरीर में मौजूद 7 चक्रों के बारे में जानने से आपको पुराने से पुराने भावनात्मक और शारीरिक चोटों को ठीक करने में मदद मिल सकती है।

मूलाधार चक्र

मूल या जड़ चक्र शरीर का पहला चक्र है और रीढ़ के आधार में स्थित है। इसका काम आपके मन, शरीर और आत्मा को पृथ्वी से जोड़ना है। यह चक्र हमें धरती के करीब होने का अहसास कराता है। यह चक्र हमें जमीन से जोड़े रखने और पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है।

स्वाधिष्ठान चक्र

यह चक्र नाभि के ठीक नीचे स्थित है. यह चक्र लसीका तंत्र से जुड़ा है और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह आपको यौन इच्छाओं या कामवासना के संपर्क में आने में भी मदद करता है।

मणिपुर चक्र

यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यह चक्र आपके मन से जुड़ा होता है. यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है।

अनाहत चक्र

हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। व्यक्ति की भावनाएं और साधना की आंतरिक अनुभूतियां इस चक्र से जुड़ी हुई हैं।

विशुद्ध चक्र

विशुद्ध चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित चक्र है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थाइराइड जैसी समस्याएं, गले और आवाज से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं।

आज्ञा चक्र

दोनों भौहों के बीच स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन मुक्त अवस्था में आ जाता है।

सहस्त्रार चक्र

मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है, उसे सहस्त्रार कहा जाता है। इस चक्र को जागृत करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए किसी योग्य गुरु की जरूरत पड़ती है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर आत्मा और शरीर दोनों मुक्ति की अवस्था में आ जाता है।

संपादकीय

बैंकों को कारोबारी होड़ में जोखिमों के प्रति सतर्क रहने का सुझाव

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने निजी और सार्वजनिक बैंकों को कारोबारी होड़ में आक्रामक रुख अपनाते हुए कर्ज के मामले में जोखिमों के प्रति सतर्क रहने का सुझाव दिया है। कई उदाहरण देते हुए उन्होंने उजागर किया कि किस तरह कुछ बैंक अपने बही-खातों में सही स्थिति दर्ज न करते हुए अपने कारोबार को तो ऊंचा दिखा देते हैं, मगर उससे उत्पन्न होने वाले खतरों से उबर पाना उनके लिए मुश्किल होता है।

रिजर्व बैंक की यह चिंता समझी जा सकती है। हालांकि बैंकों के कारोबार पर नजर रखने के लिए रिजर्व बैंक की नियामक इकाई है, जो बैंकों के बही-खातों की स्थिति का आकलन करती है। उसके बावजूद कुछ बैंक अपने कर्जों की वापसी न हो पाने के तथ्यों को छिपाते हैं। कुछ बैंक चतुराई से अपने कारोबार को ऊंचा दिखाते हैं, ताकि रिजर्व बैंक से उन्हें अपना कारोबार फैलाने की इजाजत मिल सके।

इस आधार पर वे आक्रामक तरीके से कर्ज बांटना शुरू कर देते हैं। बैंकों की मूल कमाई पर मिलने वाले ब्याज से ही होती है, इसलिए बैंक इसके लिए तरह-तरह की योजनाएं चला कर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। मगर जिस बैंक की कारोबार की जितनी क्षमता है, वह उसी के अनुरूप कर्ज देने को अधिकृत होता है। इसलिए चतुराई भरा लेखाजोखा पेश कर वे अपनी कर्ज सीमा का विस्तार करने का प्रयास करते हैं।

जब रिजर्व बैंक ने बड़े सार्वजनिक और निजी बैंकों में इस प्रकार की अनियमितता चिह्नित की है, तो छोटे बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर छोटा बैंक बड़े बैंक की श्रेणी में और एनबीएफसी बैंक बनने की कोशिश में देखी जाती है। इस तरह वे अपने कारोबार के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करती हैं।

कई सहकारी बैंक और एनबीएफसी इस तरह चालाकी से कर्ज देने के अपने दायरे को बढ़वा लेने में कामयाब रही हैं, मगर जब उनका एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्तियों का बोझ बढ़ता गया, तो वे डूब ग। पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक इसका हाल का उदाहरण है। उस बैंक ने अपने लेखाजोखा में चालाकी से विवरण दर्ज कर रिजर्व बैंक को धोखा दिया और कर्ज बांटने का अपना दायरा बढ़ाता गया। उसमें कुछ बड़ी कंपनियों को बड़े कर्ज बांटे गए। जब वे कर्ज वापस नहीं आ पाए, तो वह बैंक डूब गया। इसी तरह कई बड़े बैंक भी अपना एनपीए छिपाने का प्रयास करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वह लगातार बढ़ता जाता है।

देश के सारे सार्वजनिक बैंक एनपीए के बोझ से दबे हुए हैं। स्थिति यह है कि पिछले दस सालों में बैंकों का एनपीए बढ़ कर दो गुने से अधिक हो गया है। कई कारोबारियों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर देश ही छोड़ दिया। कई कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दरअसल, कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज को लेकर हमारे यहां नियम-कायदे इतने लचीले हैं कि लेने वालों के लिए खुद को दिवालिया घोषित कर कर्ज की रकम डकार जाना आसान लगता है। ऐसे में शक्तिकांत दास की चिंता स्वाभाविक है कि अगर बैंकों ने कर्ज बांटते समय सावधानी नहीं बरती, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मगर यह समस्या केवल नसीहत से नहीं हल होगी, रिजर्व बैंक को ही कोई सख्त रास्ता निकालना पड़ेगा।

प्रेरक कथा

किसी को भी अपना मित्र या शत्रु बनाने के लिए करें इस शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग

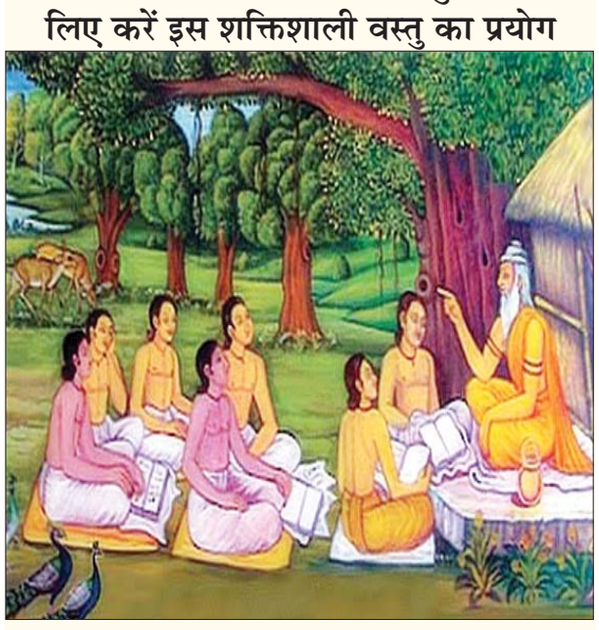

गुरुकुल के विद्यार्थियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है ? कोई कुछ कहता, कोई कुछ ! जब पारस्परिक वाद-विवाद का कोई निर्णय न निकला तो फिर सभी विद्यार्थी गुरु जी के पास पहुंचे।

गुरु जी ने शिष्यों की बात सुनकर कहा, ''तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है।'' और शांत हो गए। शिष्य गुरुदेव की इस छोटी बात को भी सहन न कर पाए और थोड़ी ही देर में उनके चेहरे तमतमा गए। अपने लाल-लाल नेत्रों से गुरु जी को घूरने लगे।

थोड़ी देर बाद गुरु जी शिष्यों से बोले, ''तुम सब पर आश्रम को गर्व है, तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं खोते, अवकाश के समय में भी ज्ञान की चर्चा करते हो।'' अब तो शिष्यों के मन में स्वाभिमान जागृत हुआ और उनके चेहरे खिल उठे।

गुरु जी ने कहा, ''मेरे प्यारे शिष्यो ! इस संसार में वाणी से बढ़कर कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से मित्र को शत्रु तथा शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है।

ऐसी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच-समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और न बनने वाला कार्य भी बन जाता है।''

तंबाकू की गिरफ्त में जकड़ता समाज

उद्धव शांडिल्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर तंबाकू सेवन से सालाना लगभग अस्सी लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें भारत में अकेले साढ़े तेरह लाख लोग इसका शिकार होते हैं।

भारत में तंबाकू से जुड़े सर्वेक्षणों के मुताबिक देश में इस्तेमाल होने वाले पूरे तंबाकू का अस्सी प्रतिशत उपभोग मुख्य रूप से गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह आंकड़ा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं की पोल खोलता है।

भारत युवाओं के संख्याबल और जनसांख्यिकीय विभाजन के कारण संभावनाओं का देश कहा जाता है। यहां की कुल जनसंख्या में अकेले बाईस प्रतिशत यानी लगभग 26.1 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ अठारह से उनतीस साल के युवाओं की है, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। मगर तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों का इस्तेमाल भारत की संभावनाओं का गला घोंटता दिखाई पड़ रहा है।

'ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे' (गैट्स) की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 26.7 करोड़ युवा, जिनकी उम्र पंद्रह वर्ष और उससे अधिक है तथा पूरी युवा जनसंख्या का 29 प्रतिशत है, तंबाकू उत्पादों का सेवन करता है। तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों के इस अंधाधुंध उपयोग ने भारत को विश्व में चीन (तीस करोड़) के बाद दूसरे सबसे बड़े तंबाकू उपभोक्ता देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर तंबाकू सेवन से सालाना लगभग अस्सी लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें भारत में अकेले साढ़े तेरह लाख लोग इसका शिकार होते हैं। भारत में पुरुषों और महिलाओं में होने वाले कैंसर का क्रमशः आधा और एक-चौथाई कैंसर तंबाकू और इससे निर्मित पदार्थों के सेवन से होता है।

अब तक के शोधों के मुताबिक तंबाकू में बेंजीन, निकोटीन, हाइड्रोजन सायनाइड, अल्डीहाइड, शीशा, आर्सेनिक, टार और कार्बन मोनो आक्साइड आदि जैसे सत्तर प्रकार के खतरनाक तत्त्व शामिल होते हैं, जिनका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण (एनसीआरआइ) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-16 के बीच कैंसर के कुल मामलों में 27 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तंबाकू से संबंधित थे।

तंबाकू शरीर के परिवहन तंत्र के संरक्षक हृदय को भी बहुत प्रभावित करता है, जिसके कारण कार्डियोवस्कुलर बीमारियां और दिल के दौरे की आशंका अधिक बढ़ जाती है। तंबाकू का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत घातक होता है। यह हमारी कल्पनाशीलता, मानसिक चेतना और स्थिरता को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण सुस्ती और पक्षाघात जैसी खतरनाक बीमारी के झटके भी आते हैं।

तंबाकू से प्रभावित होने वाले शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों में फेफड़ा भी शामिल है। तंबाकू का निरंतर उपयोग हमारे फेफड़ों की कार्यशैली को घटाता है। इससे फेफड़ों का कैंसर तथा 'क्रोनिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी' बीमारी भी होती है। आधुनिक तकनीकी युग में ई-सिगरेट की मांग भी भविष्य में होने वाली एक गंभीर समस्या को इंगित करती है।

ई-सिगरेट मुख्य रूप से एक औजार है, जिसमें एक द्रव को एरोसोल बनाने के लिए गर्म किया जाता है, जिसे तंबाकू उपभोक्ता कश लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। भले इस पर अभी शोध होने हैं और आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं, पर बच्चों द्वारा इसका प्रयोग उनमें हृदय और फेफड़ों की बीमारी को बढ़ावा देता है। तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों ने देश के कई महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी अपने चंगुल में फांस लिया है।

मनाली, कसौल, शिमला, ऋषिकेश, हरिद्वार और बनारस जैसे महत्त्वपूर्ण भारतीय पर्यटन स्थलों पर बड़ी आसानी से लोग तंबाकू का सेवन करते मिल जाएंगे। इनमें विदेशी यात्रियों का प्रतिशत अधिक है और यह हमारे यहां के कमजोर तंबाकू कानूनों के क्रियान्वयन का परिचायक है। साथ ही धर्म की आड़ में तंबाकू का कालाबाजार अपने चरम पर पहुंच गया है।

भारत ने तंबाकू की भयावहता को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसके लिए अनेक ठोस कदम भी उठाए हैं। भारत में तंबाकू नियंत्रण हेतु वर्ष 2001 में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। फिर वर्ष 2003 में 'सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम' पारित किया गया, जिसे 'कोटपा' भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिषेध तथा इसके व्यापार, वाणिज्यिक उत्पादन और वितरण का विनियमन करना था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2003 में तंबाकू नियंत्रण पर डब्लूएचओ रूपरेखा समझौता पारित किया। यह समझौता मुख्यतः तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने से संबंधित है। भारत इस समझौते में शामिल है तथा इसने 2016 में ग्रेटर नोएडा में इस प्रोटोकाल में शामिल पक्षों का एक सम्मेलन काप-7 भी आयोजित किया था।

तंबाकू नियंत्रण के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला सामूहिक स्वास्थ्य समझौता है, जिसके अंतर्गत तंबाकू और इससे संबंधित उत्पाद बनाने के लिए अनुज्ञप्ति, यंत्र-समूह के लिए उचित उद्यम और सुरक्षा आदि शामिल है। इस समझौते का अनुच्छेद 13 तंबाकू के प्रचार, अनुच्छेद 15 तंबाकू का अवैध व्यापार और अनुच्छेद 16 तंबाकू उत्पादों का अवयस्कों को और उनके द्वारा विक्रय से संबधित है।

वर्ष 2007-08 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) भी चलाया, जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिला था। तंबाकू के उपभोग से बचने तथा इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2011 में भारत सरकार के 2009 की अधिसूचना में संशोधन प्रस्तुत करते हुए एक नियम बनाया, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर चार नए चित्र चेतावनी को शामिल किया गया। इस नियम के तहत कंपनियों को अपने तंबाकू उत्पादों पर चार चित्रों के समूह में से किसी एक चित्र को उन उत्पादों पर लगाना अनिवार्य है। कुछ ऐसा ही नियम जीएचडब्लू (ग्राफिक हेल्थ वार्निंग) या आरए नंबर-10643 के रूप में फिलीपींस ने जुलाई 2014 में पारित किया था।

तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए भारतीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा डब्लूएचओ के सहयोग से 'तंबाकू निवारण क्लिनिक' की स्थापना एक अभूतपूर्व प्रयोग है। ऐसे क्लिनिक तंबाकू के स्वास्थ्य ह्रास परिणाम से जूझ रहे लोगों को वैज्ञानिक तरीके से तंबाकू छोड़ने में मदद करते हैं।

2003 में 'सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम' के प्रावधानों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण हेल्पलाइन की स्थापना भी एक अद्वितीय विधि है। सांख्यिकी आंकड़े बताते हैं कि इस हेल्पलाइन पर प्रतिमाह एक हजार से अधिक फोन आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में उपभोग किए जाने वाले तंबाकू के लगभग 69 प्रतिशत पर कोई कर नहीं लगाया जाता। करों के माध्यम से भी तंबाकू की कालाबाजारी, अवैध व्यापार और संवर्धन को नियंत्रित किया जा सकता है। तंबाकू प्रभाव निरोध हेतु सिविल सोसायटी की भूमिका भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

भारत में तंबाकू से जुड़े सर्वेक्षणों के मुताबिक देश में इस्तेमाल होने वाले पूरे तंबाकू का अस्सी प्रतिशत उपभोग मुख्य रूप से गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह आंकड़ा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं की पोल खोलता है।

जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर तेंदू के पत्तों से चल रहे बीड़ी उद्योग में लगे लोगों को अन्य जंगली उत्पादों जैसे, शहद, लकड़ी और भोज्य साम्रग्री पर आधारित एक 'जंगली उत्पाद विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत उद्योग में स्थानांतरित कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, जिससे भारत में तंबाकू उत्पादन को कम किया जा सकता है।

ऐसे प्रयोग से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के क्रमशः प्रथम, नौवें और दसवें लक्ष्य जैसे शून्य गरीबी, उद्योग और नवाचार तथा असमानताओं में कमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर तंबाकू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा संसद और शौच मुक्ति के लिए आयोजित शौचालय संसद की भांति 'तंबाकू संसद एवं तंबाकू पंचायत' को भी आयोजित किया जा सकता है।

लोगों को गरीब बनाता महंगा इलाज

देश में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी ही नहीं होती जा रहीं, मरीजों को गरीब भी बना रही हैं।

जयप्रकाश त्रिपाठी

चिकित्सा खर्च इस कदर जेब पर भारी पड़ रहा है कि हर साल कर्ज लेकर, संपत्तियां बेचकर इलाज कराने वाली सात-आठ प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाती है। तैंतालीस फीसद कमाई इलाज पर खर्च हो जा रही है। ऐसे ज्यादातर मरीज कैंसर, हृदय और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं।

देश में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी ही नहीं होती जा रहीं, मरीजों को गरीब भी बना रही हैं। लगातार बढ़ता चिकित्सा खर्च हर साल सात प्रतिशत आबादी को गरीबी रेखा के नीचे धकेल रहा है। आक्सफैम इंटरनेशनल की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत के अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर दो फीसद की दर से एकमुश्त कर लगा दिया जाए, तो उसी राशि से देश में तीन साल तक कुपोषितों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत पूरी की जा सकती है। इसी तरह देश के दस सबसे अमीर अरबपतियों पर पांच प्रतिशत का एकमुश्त कर लगा कर साल भर के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बजट की अच्छी-खासी भरपाई हो सकती है।

हमारे देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र योजना, जननी सुरक्षा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) योजना, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, राज्यों में 108 एंबुलेंस सेवा, इंद्रधनुष टीकाकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता जैसी अनेक आधारभूत व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (प्रजनन) आदि सरकारी इंतजामात के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा (सालाना औसतन 11 लाख) नवजात बच्चों की मौतें भारत में हो रही हैं।

हर साल दस लाख नवजात शिशुओं को गंभीर एचबीवी संक्रमण का खतरा रहता है। पैदा होने वाले प्रति एक हजार में से औसतन उनतीस नवजात की मौत हो जाती है। 'सेव द चिल्ड्रेन' संस्था के मुताबिक, विश्व में नवजात शिशुओं की कुल मौतों में से उनतीस फीसद अकेले भारत में होती हैं।

गरीब परिवारों के लिए यह सच कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे अपने बच्चों के इलाज का खर्च उठाने लायक नहीं रह गए हैं। अस्पतालों में भर्ती बच्चों पर केंद्रित एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रति सौ परिवारों में से तेरह को इलाज में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ज्यादातर परिवार अगली धार के कार्यकर्ताओं, जैसे आशा, आंगनबाड़ी, सहायक नर्स मिडवाइव्स की पहुंच से भी वंचित हैं।

आयुष्मान भारत योजना के साथ भी पहुंच का सवाल जुड़ा है। बेतहाशा महंगे दवा-इलाज ने तेईस फीसद मरीजों को चिकित्सा से वंचित कर दिया है। सत्तर फीसद लोग अपनी जेब से इलाज करा रहे हैं। मेडिकल कालेजों, अस्पतालों, प्रशिक्षित डाक्टरों और नर्सों की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाएं तो पहले से ही चरमराई हुई हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी खर्च एक दशक से ऊंट के मुंह में जीरा की तरह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.3 प्रतिशत पर ही टिका हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का हाल यह है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भूटान, श्रीलंका और नेपाल जैसे गरीब देशों का भी सालाना खर्च भारत से ज्यादा है। देश में आबादी सात गुना बढ़ गई, पर स्वास्थ्य सुविधाएं दोगुनी भी नहीं हो सकी हैं।

देश के कुल लगभग सत्तर हजार अस्पतालों में से साठ फीसद में तो पर्याप्त बिस्तर तक नहीं हैं। आनुपातिक तौर पर प्रति पैंसठ मरीज पर मात्र एक बिस्तर की उपलब्धता है। चिकित्सा खर्च इस कदर जेब पर भारी पड़ रहा है कि हर साल कर्ज लेकर, संपत्तियां बेचकर इलाज कराने वाली सात-आठ प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाती है। तेंतालीस फीसद कमाई इलाज पर खर्च हो जा रही है। ऐसे ज्यादातर मरीज कैंसर, हृदय और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की न तो फिलहाल दस करोड़ परिवारों तक पहुंच बन पाई है, न प्राथमिक उपचार के लिए पूर्व घोषित डेढ़ लाख 'हेल्थ ऐंड वेलनेस' केंद्र बन सके हैं।

एक तो निजी अस्पताल आयुष्मान योजना की तय सरकारी दरों पर इलाज के लिए सहमत नहीं हैं। दूसरे, पर्वतीय प्रदेशों को छोड़ कर अन्य राज्य इस योजना के तहत चालीस प्रतिशत इलाज का खर्च उठाने से कतराते हैं। बंगाल सरकार ने तो आयुष्मान भारत योजना को राज्य की स्वास्थ्य योजना में मिश्रित कर दिया है। नतीजे स्पष्ट हैं कि योजनाएं कागजी होकर रह गई हैं। देश की सवा अरब से अधिक आबादी के लिए स्वास्थ्य का मौजूदा ढांचा नितांत अपर्याप्त हो चला है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर 1990 के बाद से, देश में पता नहीं कितने अभियान, कार्यक्रम, नीतियां और निवेश सामने आ चुके हैं, तब भी स्वास्थ्य क्षेत्र में हालात जस के तस बने हुए हैं। देश में मानव संसाधनों का पारदर्शी इस्तेमाल न हो पाना भी इस विफलता की एक खास वजह है। अन्य क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र के संसाधन भी मुट्ठी भर शक्तियों के हाथों में सिमट कर रह गए हैं। किसी जमाने में चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता था, पर अब इस पेशे ने नई तकनीकों से लैस होकर बाजार का बाना ओढ़ लिया है।

सरकारें और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दें तो गरीबों का निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकता है। ऐसे मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में दस फीसद आरक्षित बिस्तर मुहैया कराने का स्पष्ट प्रावधान है। 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गरीब मरीजों को आरक्षित बिस्तर उपलब्ध न कराने पर अस्पतालों पर भारी जुर्माने का निर्णय दिया था। लगभग एक दशक पहले दिल्ली सरकार भी इस दिशा में पहल कर चुकी है।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियों के आकलन और उसके आधार पर भारत में चिकित्सा व्यवस्थाएं बनाने के लिए सन 1946 में जोसेफ विलियम भोरे के नेतृत्व में बनाई गई समिति ने प्रति चालीस हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का सुझाव दिया था। प्रत्येक पीएचसी में दो डाक्टर, एक नर्स, चार सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, चार दाइयां, दो स्वच्छता निरीक्षक, दो स्वास्थ्य सहायक, एक फार्मासिस्ट और पंद्रह अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शामिल करने का सुझाव था।

इस प्रस्ताव को 1952 में भारत सरकार ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सभी सिफारिशें लागू नहीं हो सकीं। 1970 के दशक में डब्लूएचओ ने 'सभी के लिए सेहत' लक्ष्य निर्धारित किया। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज विकसित हुए, बड़े-बड़े स्वास्थ्य संस्थान बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरतों के अनुकूल विकसित नहीं किया जा सका है। आज एम्स, पीजीआई जैसे बड़े संस्थान उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं।

कहीं घूम आये

चल यार कहीं घूम आयें
बोरियत भगाये, रिफ्रेश होकर आए
ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों में चढ़े
ताजी ताजी सांसे भर लाये,
झरझर गिरते झरने के
नीचे बैठ जायें,
ऊपर से गिरती बूंदों को गले लगाएं,
कलकल बहती नदियां
कुछ कहती चल सुन आये,
इनकी मधुर ध्वनि रगो में
जोश जगाये,
बर्फीले पहाड़ों से कुछ
ठंडक चुरा लायें,
ऊंची-ऊंची चोटियों पर
अपने निशां छोड़ आये
समन्दर की लहरे
अपनी कहानी सुनाये
चुपचाप किनारे पर बैठकर
चलो उंगलियों से नाम लिख आये
हरे भरे जंगल पुकारते हैं हमें,
पेड़ों से इनके साखों से
चलो दोस्ती कर आये
कितनी सुंदर है फूल खिले
उन पर ये कोमल कोमल
तितलियां मंडराये
इन रंगों को जीवन में बरकर
चलो एक नया इंद्रधनुष बनाये
सैर कर आये रेगिस्तान की
कदमों से अपने चलों
कुछ मील नाप आये
विरासत में मिले महल, किला
और अन्य धरोहर को देख आये
अपने पूर्वजों की निशानी को
चलो स्पर्श कर आये,
चल यार कही घूम आये
बोरियत भगाये रिफ्रेश होकर आये

डॉ. शशिकांत सिंह राजपूत
रायपुर

नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांग के लिए अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन 11 जून को

रायपुर। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा नियमित भर्ती पर रोक लगाने सहित अपनी 5 सूत्रीय मांग यथा नियमितीकरण, पृथक कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग/ठेका बंद करने एवं दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर 11 जून को तुता नवा रायपुर में धरना-प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव करेगा।

उक्त जानकारी देते हुए प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिवस में प्राथमिकता से अनियमित कर्मचारियों के मांगों को पूरा करने का वादा किया7 इसी प्रकार कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र 'दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा' के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने एवं आउट सोर्सिंग बंद करने तथा पृथक कर्मचारियों को रोजगार देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने 14 फ़रवरी 2019 को अनियमित मंच से घोषणा किये की यह वर्ष किसानों का है आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा7 मार्च 2019 में बनी समिति अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी? जुलाई 2019 से शासन अभी तक अनियमित कर्मचारियों की आंकड़े प्राप्त नहीं कर सकी? आउट सोर्सिंग बंद नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार अपने वादे के विपरीत 10 हजार से अधिक अनियमित कर्मचारियों यथा स्कुल सफाई कर्मचारी, महिला पुलिस वालेंटियर, अतिथि शिक्षकों, शिक्षण सेवक, स्वस्थ्य कर्मचारियों, ग्रामीण विकास विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों की छटनी कर दी गई एवं छटनी निरंतर जारी है, मार्च 2017 के पश्चात् न्यूनतम वेतन एवं अगस्त 2019 के पश्चात् संविदा वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं की गई

सरकार नौकरी तिहार मना रही है? और विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग पशुधन विकास विभाग, सहकारिता विभाग में वर्षों से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को निकाले जाने के भय से जीवन जीने विवश हो रहा है7 शिक्षा विभाग अंतर्गत बीजापुर सुकमा में 301 शिक्षा दूत, बीजापुर में 70 शिक्षा मितान, बस्तर 160 शिक्षण सेवक, कोंडागांव में 508 ट्यूटर शिक्षक, दंतेवाडा, कांकेर, नारायणपुर, मुंगेली में 1185 स्थानीय अतिथि शिक्षक, कबीरधाम में 126 शाला संगवारी, मदरसा अतिथि शिक्षक 1005, एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक 386 इन्हें भर्ती में किसी प्रकार की वेटेज नहीं दी जा रही है केवल 1659 अतिथि शिक्षक (विद्या मितान) जो उच्चतर शाला में कार्यरत उन्हें वेटेज दी जा रही है जबकि अधिकांश अतिथि शिक्षक (विद्या मितान) के पास टेट प्रमाण-पत्र नहीं होने से ये फार्म भर ही नहीं पाएंगे7 इसी प्रकार आई.टी.आई. में कार्यरत 350 प्रशिक्षण अधिकारी एवं 750 मेहमान प्रवक्ता, वन विभाग में सहायक प्रबंधक एवं कार्यालयीन संवर्ग के अनियमित कर्मचारी 576, सहकारिता विभाग के 522 से अधिक अनियमित कर्मचारी प्रभावित होंगे7 कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी से अनियमित कर्मचारियों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

5 सूत्रीय मांगों में समस्त अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, निकाले गए अनियमित कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे, आउट सोर्सिंग/ठेका बंद किया जावे, दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति शामिल है।

छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से अपील करता है कि 11 जून को आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव में अधिक से अधिक सम्मिलित होकर आन्दोलन को सफल बनावे एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता है कि नियमित भर्ती बंद कर घोषणा पत्र में किये गए वादे के अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें।

धुर नक्सल प्रभावित अंतिम छोर पर बसे गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंचे अधिकारी

कांकेर। जिले के धुर नक्सल प्रभावित अंतिम छोर पर बसे गांव में आजादी के बाद पहली बार प्रशासन और उनके नुमाइंदे पहुंचे। जहां ग्रामीणों की कई समस्याओं का निवारण किया गया।

कांकेर जिला बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जिला है। नक्सल प्रभावित इस जिले के कुछ इलाके ऐसे हैं। जिनमें नक्सलियों की काफी पैठ है। उन्ही में से एक है बण्डापाल। जिले के अंतिम छोर में बसे इस धुर नक्सल प्रभावित गांव में ऐसा पहली बार हुआ। जब आजादी के बाद प्रशासन उन तक खुद चल कर पहुंचा। नक्सलियों की दहशत इतनी है विकास के कार्यो को गति देना अंदरूनी इलाकों में प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं।

अब तक जहां कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच सका। वहां एक महिला कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला अपनी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ वहां पहुंच कर ग्रामीणों से रूबरू हुए। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंची। शिविर में लगभग 4 से अधिक गांव के ग्रामीण एकत्रित हुए। जिनसे प्राप्त हुए 136 आवेदन में 13 का तत्काल मौके पर निराकरण भी किया गया। ग्रामीणों की मांग और जरूरतों के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, बोरखनन, पीडीएस गोदाम सहित अन्य कार्यो के लिए लाखों रुपये की स्वीकृति भी त्वरित रूप से प्रदान की गई। जिससे ग्रामीण बेहद खुश नजर आए।

ग्राम बण्डापाल घोर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। आज तक जहां कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाया था। वहां माह दिसम्बर 2022 के अंत में एक महिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच पहुंच ना केवल उनकी समस्या सुनी थी। बल्कि उसे दूर करते हुए दुबारा जल्द आने का भरोसा दिया था। जिसे आज पूरा करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि मेरे साल भर के कार्यकाल का यह सबसे अविस्मरणीय क्षण है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं कभी इस गांव में आई थी। कांकेर जिले के सबसे अच्छे डॉक्टर यहां मौजूद हैं, सभी लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करायें। इस अवसर पर जल जीवन मिशन, कृषि और जनपद कार्यालय द्वारा स्टॉल लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया गया। साइकिल का वितरण किया गया।

ग्रामीणों की मांग के अनुरूप विभिन्न घोषणाएं भी की गई। साथ उन्हें वे तमाम सुविधाएं मुहैय्या कराने का भरोसा दिया। जिनकी उन्हें आवश्यकता है। ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। ग्रामीण भी प्रशासन को अपने नजदीक पाकर बेहद खुश नजर आए। प्रशासन अगर इसी तरह के कार्य करता रहा तो वो भी दिन दूर नहीं कि नक्सल पर प्रभावित क्षेत्र के लोग सुविधाओं से महरूम रह सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग

- एआई आधारित 'छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप' किया गया है विकसित
- उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों को मोबाइल पर मिल रहा है अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए एआई आधारित 'छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप' विकसित किया गया है। पिछले 3 महिनों से उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाके में हाथियों के रियल टाईम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा रहा है। इस एप में ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन का पंजीयन किया जाता है। जब एलीफेंट ट्रैकर्स द्वारा हाथियों के मूवमेंट का इनपुट एप पर दर्ज किया जाता है, तो एप द्वारा स्वचालित रूप से ग्रामीणों के मोबाइल पर अलर्ट जाता है।

छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस एप को विकसित किया गया है। यह एप एलीफेंट ट्रैकर्स (हाथी मित्र दल) से प्राप्त इनपुट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम करता है। इस एप का उद्देश्य हाथी ट्रैकर्स द्वारा की जाने वाली 'मुनादी' के अलावा प्रभावित गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल पर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट के भेजकर हाथियों की उपस्थिति के बारे में सूचना पहुंचाना है।

वर्तमान में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व (गरियाबंद, धमतरी) के लगभग 400 ग्रामीणों को इस अलर्ट सिस्टम में पंजीकृत किया गया है और पिछले 3 महीनों से यह काम कर रहा है।

पटवारियों की हड़ताल को अधिवक्ता संघ का समर्थन

बीजापुर। अधिवक्ता संघ ने कहा कि, किसानों को खाद बीज ऋण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रजिस्ट्री या प्रशासनिक कार्य हो वो सभी हड़ताल से लटके हुए हैं। आम जनता परेशान है। सभी का काम रुका हुआ है। ऐसे में शासन को चाहिए कि पटवारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करे।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चल रही पटवारियों की हड़ताल के समर्थन में अब अधिवक्ता संघ भी आ गया है। मंगलवार को अधिकक्ता संघ के पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और पटवारियों के समर्थन में नारेबाजी की। साथ ही कहा कि, पटवारियों की मांग जायज है। उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। पटवारी अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर 23 दिनों से हड़ताल पर हैं।

प्रदेश में पटवारियों का हड़ताल 15 मई से जारी है। अधिवक्ता संघ ने पटवारियों की सभी मांगों को जायज बताया है। कहा कि, न्यायालय से संबंधित बहुत सारे प्रकरण हैं, जिन पर पेशियां लंबित है। पटवारियों का प्रतिवेदन नहीं आने की वजह से उन पर फैसले लटके हुए हैं। अभी स्कूली बच्चों का एडमिशन का समय है। जिसमें जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

अधिवक्ता संघ ने कहा कि, किसानों को खाद बीज ऋण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रजिस्ट्री या प्रशासनिक कार्य हो वो सभी हड़ताल से लटके हुए हैं। आम जनता परेशान है। सभी का काम रुका हुआ है। ऐसे में शासन को चाहिए कि पटवारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करे। बहुत से पटवारी 30 साल से एक ही पद पर पदस्थ हैं। उनका प्रमोशन लंबित है।

पटवारियों के समर्थन में पहुंचने वालो मे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पी वेणुगोपाल राव, सचिव शेख सलीम पाशा, लक्ष्मीनारायण गोटा, और सूर्यनारायण रेड्डी, सल्लूर वेंकटी, रामदास कश्यप, ईश्वरी झाड़ी और सैफ अली खान शामिल रहे। वरिष्ठ पटवारी संघ के संरक्षक शंकर लाल कतलाम ने 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, बार संघ के अध्यक्ष को सौंपा और समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया।

सारथी ऐप से अब नागरिक घर बैठें अपनी शिकायतें शासकीय विभागों तक पहुंचा सकेंगे

दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है सारथी ऐप

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित होने वाले भरोसे के सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ किया। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार कराए गए इस मोबाईल ऐप के माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज व ट्रैक कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक शासन के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और समस्याओं का संबंधित विभागों द्वारा त्वरित निराकरण किया जाएगा।

सारथी ऐप को मोबाइल के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते ही उसे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

प्राप्त आईडी में व्यक्ति लॉगिन कर अपनी समस्या को दिए गए फॉर्मेट में अंकित कर अपने आवेदन को सबमिट करेगा।

ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत होगी। जिसमें नोडल अधिकारी संबंधित विभाग को आवेदन फॉरवर्ड करेगा। प्राप्त आवेदन पर संबंधित विभाग को नियत समय पर दर्ज शिकायत का निराकरण करना होगा। जिसकी ट्रैकिंग आवेदक घर बैठे ही मोबाइल एप के द्वारा कर सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की जनसुविधा को ध्यान में रखकर यह जिलास्तरीय ऐप बनाया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर यह मोबाइल एप्लीकेशन SAARTH&E नाम से उपलब्ध है।

मितान बन 5500 वां कार्ड लेकर कलेक्टर सिन्हा पहुंचे हितग्राही के घर

रायगढ़ नगर निगम में एक वर्ष में 5 हजार 500 आवेदनों का हुआ निराकरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को घर बैठे ही अपने जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनकर मिल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कबीर चौक निवासी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने राशन कार्ड बनवाने 14545 पर कॉल कर 5 जून को दस्तावेज दिया और आज 7 जून को उनका कार्ड तैयार हो गया। जिसे देने कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा खुद मितान बनकर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल और श्रीमती सुलोचना देवी अग्रवाल के घर पहुंचे और उन्हें उनका राशन कार्ड सौंपा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी उपस्थित रहे। श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कलेक्टर खुद मितान बनकर कार्ड देने आयेंगे। उल्लेखनीय है कि यह निगम क्षेत्र में मितान योजना के तहत निराकृत किया गया 5 हजार 500 वां प्रकरण था।

इस मौके पर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने के लिए मितान योजना की शुरुआत की गई है। रायगढ़ निगम क्षेत्र में आज 5500 वें दस्तावेज की डिलीवरी आज की जा रही है। इसके तहत आज हितग्राही को उनका राशन कार्ड बनाकर दिया गया है। राशन कार्ड की यह सुविधा हाल ही में मितान योजना के तहत शामिल की गई है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि योजना का उद्देश्य है कि लोगों को घर बैठे प्रमाण पत्र व दस्तावेज बनाकर दिए जाएं। इसके लिए उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े। इस बारे में श्री ओमप्रकाश अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सिर्फ एक कॉल से उनका राशन कार्ड तैयार हो गया जिसे देने खुद जिले के कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 5 तारीख को उन्होंने सारे दस्तावेज दिए और आज राशन कार्ड बनकर घर पहुंच गया। इसके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नागरिक सुविधाओं को एक कॉल पर लोगों के घर तक पहुंचाने वाली इस सुविधाजनक योजना के लिए बहुत बहुत आभार जताया।

एक साल में 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 1 मई 2022 को प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पिछले एक साल में विभिन्न सुविधाओं के तहत 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।

मितान योजना से श्रम और समय की हो रही बचत

मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि की रिकार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार और दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया: बघेल

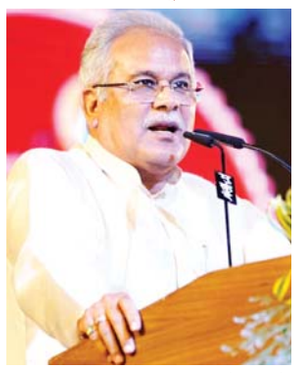

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल केशकाल विकासखंड के ग्राम बेड़मा में आयोजित डड़सेना-कलार सामाज के संभाग स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मां दंतेश्वरी, भगवान सहस्त्रबाहु, बहादुर कलारिन और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डड़सेना-कलार समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को समर्थन मूल्य में 65 प्रकार की वनोपज खरीदी के लिए महुए के फूल से तौलकर आभार जताया। साथ ही सामाजिकजनों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने डड़सेना-कलार समाज के लिए केशकाल में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया है। देवगुड़ी, माता गुड़ी, पेन गुड़ी का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही आदिवासी आस्था स्थलों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन कर रहे हैं। जिसमें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कलाकार पहुंचते हैं, जिससे हमारी एक अलग पहचान बनी है। इसके साथ ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हाल ही में हमने रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का सफल आयोजन किया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां रामायण पर इतना भव्य आयोजन हुआ और देश ही नहीं विदेश के कलाकार भी इसमें शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में हमने बड़े फैसले लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। किसानों का ऋण माफी किया।

अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए नियम

नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी है। इस अधिसूचना के मुताबिक ओटीटी प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश दिखाना अनिवार्य है। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अधिसूचना विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) पर जारी की है, जिसके बाद सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में पहले से ही तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य है। फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड की अवधि की तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है।

नए नियम के अनुसार, तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता दिखाएगा। साथ ही ओटीटी प्लेटफार्मों को तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या कार्यक्रम में उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी दिखानी होगी।

तंबाकू के दुष्प्रभावों पर 20 सेकेंड का डिस्क्लेमर

सूत्रों ने कहा कि साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा। अधिसूचना में कहा गया है, ''तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरो में 'तंबाकू से कैंसर होता है' या 'तंबाकू जानलेवा है' की चेतावनी दिखानी होगी जो स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।'' इसके अलावा, तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी भाषा में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है।

ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन या उनका उपयोग सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद का प्रचार और तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन या प्रचार सामग्री में उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

राज्य में तेजी से खोले जा रहे परिवहन सुविधा केन्द्र

- **अब तक 451 परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापित**
- **अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की नहीं होगी जरूरत**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में अब तक 451 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्यभर में 1000 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी। परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना से एक ओर जहां परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, वहीं लोगों को इसके संचालन के जरिए रोजगार भी उपलब्ध होगा। राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना से करीब 5 हजार युवाओं के रोजगार सृजन की सम्भावना है।

इसके तहत परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन और सचिव परिवहन श्री एस. प्रकाश के निर्देशन में राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना तेजी से जारी है। इस संबंध में आयुक्त परिवहन श्री दीपांशु काबरा ने बताया कि राज्यभर में अब तक 451 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इनमें जिला परिवहन कार्यालय रायपुर के अंतर्गत 54, कांकेर अंतर्गत 11, राजनांदगांव अंतर्गत 26 तथा रायगढ़ अंतर्गत 34 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना शामिल हैं। इसी तरह महासमुन्द जिला परिवहन कार्यालय के अंतर्गत 17, धमतरी अंतर्गत 28, जांजगीर-चांपा अंतर्गत 27, जगदलपुर अंतर्गत 8, बैकुण्ठपुर अंतर्गत 7, अंबिकापुर अंतर्गत 14 तथा सूरजपुर अंतर्गत 10 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा कोण्डागांव अंतर्गत 9, कबीरधाम अंतर्गत 18, गरियाबंद अंतर्गत 17, सुकमा अंतर्गत 10, बलरामपुर अंतर्गत 10, जशपुर अंतर्गत 9, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत 8, कोरबा अंतर्गत 14, मुंगेली अंतर्गत 12, बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत 17, बालोद के अंतर्गत 11 और दंतेवाड़ा अंतर्गत 7, दुर्ग अंतर्गत 40, बेमेतरा अंतर्गत 6 तथा बिलासपुर अंतर्गत 27 केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है।

सुविधा केन्द्रों के द्वारा आवेदकों से ली जा सकेगी निर्धारित फीस

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है। मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है।

मार्गदर्शिका के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये, परिवहन विभाग को ऑनलाइन फीस/टैक्स भुगतान करने के लिए (प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए) 50 रुपये, लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क 50 रुपये, आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की स्कैनिंग, कम्प्रेसिंग व अपलोड (प्रति पेज) 5 रुपये तथा ऑनलाइन आवेदन पूर्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का प्रिंटआउट शुल्क (प्रति पेज) 5 रुपये निर्धारित है।

अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को होगा। अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन करते रहे हैं। जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ में अब तक तीन चौथाई तेंदूपत्ता का संग्रहण पूर्ण

16.72 लाख मानक बोरा के लक्ष्य के विरूद्ध 12.27 लाख मानक बोरा संग्रहित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 के दौरान अब तक 12 लाख 27 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है, जो लक्ष्य के 75 प्रतिशत के करीब है। ज्ञातव्य है कि राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16 लाख 72 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वनांचल के आदिवासी-वनवासियों द्वारा तेंदूपत्ता का संग्रहण कार्य तेजी से जारी है।

प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल राय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक संग्रहित मात्रा में से वनमण्डल बीजापुर में 73 हजार 99 मानक बोरा तथा सुकमा में एक लाख 19 हजार 243 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण शामिल है। इसी तरह वनमण्डल दंतेवाड़ा में 15 हजार 630 मानक बोरा, जगदलपुर में 20 हजार 971 मानक बोरा, दक्षिण कोण्डागांव में 18 हजार 608 मानक बोरा तथा केशकाल में 24 हजार 963 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। वनमण्डल नारायणपुर में 18 हजार 485 मानक बोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर में 90 हजार 649 मानक बोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 32 हजार 196 मानक बोरा, तथा कांकेर में 33 हजार 342 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।

इसी तरह वनमण्डल राजनांदगांव में 60 हजार 569 मानक बोरा, खैरागढ़ में 24 हजार 49 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। बालोद में 19 हजार 17 मानक बोरा, कवर्धा में 32 हजार 97 मानक बोरा, वनमण्डल धमतरी में 20 हजार 584 मानक बोरा, गरियाबंद में 77 हजार 570 मानक बोरा, महासमुंद 70 हजार 78 मानक बोरा तथा बलौदाबाजार 15 हजार 949 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है। वनमण्डल बिलासपुर में 25 हजार 200 मानक बोरा, मरवाही 10 हजार 683 मानक बोरा, जांजगीर-चांपा में 6 हजार 881 मानक बोरा, रायगढ़ में 49 हजार 23 मानक बोरा, धरमजयगढ़ में 70 हजार 861 मानक बोरा, कोरबा में 43 हजार 705 मानक बोरा तथा कटघोरा में 56 हजार 844 मानक बोरा का संग्रहण हुआ है। इसी तरह वनमण्डल जशपुर में 27 हजार 291 मानक बोरा, मनेन्द्रगढ़ 22 हजार 530 मानक बोरा, कोरिया में 15 हजार 626 और सरगुजा में 20 हजार 595 मानक बोरा, बलरामपुर में 71 हजार 156 मानक बोरा, सूरजपुर में 39 हजार 148 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।

गोबर पेंट से बनी पेंटिंग लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा गोबर पेंट से एक घंटे में 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई। जिसे 'गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग' के रूप में 'लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर इको क्लब के विद्यार्थियों ने 'इनवेस्ट इन आवर प्लैनेट' थीम पर लाईफ अभियान के तहत एक घंटे में यह पेंटिंग बनाई थी। यह पेंटिंग राजधानी रायपुर के एक मॉल में 100 से अधिक बच्चों ने बनाई थी। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर 2 दिवसीय जागरूकता अभियान भी चलाया गया था।

बढ़ती डिमांड के चलते किसान ले रहे रागी की खेती में रूचि

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए मिलेट मिशन का सार्थक परिणाम दिखने लगा है। किसान अब धान की खेती के बदले रागी और कोदो, कुटकी की फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बेमेतरा जिले में लगभग 500 हेक्टेयर में किसानों ने पहली बार धान के बदले रागी की फसल ली है।

छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो-कुटकी की समर्थन मूल्य पर 3000 प्रति क्विंटल की दर से तथा रागी की खरीदी 3377 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जा रही है। साथ ही धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा धान के बदले खरीफ की अन्य फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी की फसल लेने पर 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम जिया निवासी श्री घनश्याम वर्मा अपने 5 एकड़ खेत में बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत रागी फसल की खेती कर रहे हैं तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज निगम पथर्रा में पंजीकृत हैं। जिले में पूर्व वर्षो में मिलेट अंतर्गत रागी फसल का रकबा निरंक था किंतु इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत जिले में पहली बार 550 हेक्टेयर में रागी फसल की खेती की गई है तथा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत् किसानों का पंजीयन भी कराया गया है। इस प्रकार प्रमाणित रागी बीज की उपलब्धता से जिले को आत्मनिर्भर बनाने तथा रागी फसल का रकबा में वृद्धि करने का प्रयास किया गया।

रागी की बढ़ती डिमांड

पोषक तत्वों के कारण मिलेट अनाजों की लगातार डिमांड अचानक से बढ़ रही है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए किसान भी इन फसलों को उपजा रहे हैं। रागी, जिसका दूसरा नाम मडुआ भी है, छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मिलेट मिशन के तहत किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को उन्नत बीज के साथ अन्य सहायता दी जा रही है। मंडी में रागी की कीमत भी काफी अच्छी मिल रही है और साथ ही इसकी खेती करना ज्यादा कठिन भी नहीं है। यानी रागी की खेती कर किसान कम मेहनत के ही अच्छी कमाई कर सकते हैं।

रागी फसल के फायदे

रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पायी जाती है जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती है। रागी बच्चों एवं बड़ों के लिये उत्तम आहार हो सकता है। प्रोटीन, वसा, रेशा, व कार्बोहाइड्रेट्स इन फसलों में प्रचुर मात्रा में पाये जाते है। महत्वपूर्ण विटामिन्स जैसे थायमीन, रिवोफ्लेविन, नियासिन एवं आवश्यक अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा पायी जाती है जोकि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिये आवश्यक होते है। रागी युक्त आहार कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ओस्टियोपोरोसिस से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों के आहार (बेबी फूड) हेतु विशेष रूप से लाभदायक होता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में साढ़े सात हजार कन्याओं के विवाह का लक्ष्य

- **बजट में दोगुनी वृद्धि करते हुए 38 करोड़ रूपए आबंटित**
- **गरीब परिवार की हर बेटी के विवाह पर व्यय की जाएगी 50 हजार रूपए की राशि**
- **विवाह के मौके पर कन्या को मिलेगा 21 हजार रूपए का ड्रॉफ्ट और 15 हजार रूपए का उपहार**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अब पूरे सम्मान के साथ होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है। विवाह के अवसर पर प्रत्येक कन्या को 21 हजार रूपए की राशि बैंक खाते या बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा 15 हजार रूपए की राशि के उपहार भी दिए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम छमाही में तीन हजार कन्याओं और वार्षिक आधार पर 07 हजार 500 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है, इससे कई निर्धन परिवारों का अपनी बेटियों के सम्मानजनक रूप से विवाह का सपना पूरा हो सकेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रत्येक कन्या को विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या 8 हजार रूपए, इसके साथ विवाह के मौके पर वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री इत्यादि पर 6 हजार रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विवाहित जोड़े को 15 हजार रूपए की उपहार सामग्री भी भेंट की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि में दो बार वृद्धि की है। श्री बघेल ने वर्ष 2019 में योजना के तहत सहायता राशि को 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए कर दिया था। अब 2023-24 के बजट में यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है। वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी दोगुनी करते हुए 38 करोड़ रूपए कर दी गई है।

योजना तहत देय लाभ

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र के रेत खदानों के संचालन का अधिकार अब पंचायतों को

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 19 जनवरी को जारी अधिसूचना द्वारा अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रेत खदानों के संचालन का अधिकार अब पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा रेत खदान संचालन के लिए नक्शा खसरा सहित आवेदन प्रारूप में एक हजार रूपए आवेदन शुल्क (गैर वापसी योग्य), के साथ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्रस्तुत कर सकते है। इसके लिए ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय समिति द्वारा रेत खनन क्षेत्र का चिन्हांकन कर समस्त निरीक्षण प्रतिवेदन लिये जाने के पश्चात कलेक्टर द्वारा घोषित किया जाएगा तथा उसे विशिष्ट नाम दिया जाएगा।

खदान घोषित किये जाने के 15 दिवस के भीतर संबंधित पंचायतों को 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर या उसके किसी भाग के लिए कार्यपालन प्रतिभूति राशि चालान के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् कलेक्टर द्वारा आशय पत्र जारी किया जाएगा। संबंधित पंचायत को 1 वर्ष के भीतर अनुमोदित उत्खन्न योजना, पर्यावरण स्वीकृति, अन्य आवश्यक सहमति और अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के पश्चात् 5 वर्षों के लिए रेत खदान हेतु पट्टा प्रदान किया जाएगा। पट्टा प्राप्त होने पर 90 दिवस के भीतर अनुबंध कराया जाएगा। पंचायतों को निर्धारित रेत रायल्टी, उच्चतम निर्धारित मूल्य प्रति घनमीटर की दर से सीधे पंचायत राज के शीर्ष में, 10 प्रतिशत डीएमएफ की राशि, पर्यावरण एवं विकास उपकर और टीसीएस की राशि संबंधित खातों में जमा कर चालान खनिज शाखा में प्रस्तुत करने पर रेत परिवहन हेतु अभिवहन पास जारी किया जाएगा।

यदि ग्राम पंचायतें रेत खदानों का संचालन करने में रूचि नहीं लेते हैं तो उसी पंचायत के यथा स्थान पंजीकृत स्व सहायता समूह अथवा स्थानीय बेरोजगार को कोऑपरेटिव सोसायटी द्वारा रेत खदान संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन भी आवश्यक होगा। इस प्रकार आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर, जिला कार्यालय एवं जिला स्तरीय समिति के माध्यम से आवेदन पर विचार करने के पश्चात् उन्हें खदान संचालन हेतु अधिकृत करेंगे। बिना विधिमान्य प्राधिकार के रेत खदानों से या अन्य क्षेत्रों से अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने पर खान एवं खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत की कार्रवाई की जाएगी।

नोटबंदी का एक और चाबुक

काले धन को सफेद करने का तरीका ?

2016 में 8 नवंबर को रात आठ बजे टीवी पर आकर जिस प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीपक को हटाने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी और ये बताया था कि आज रात 12 बजे से पांच सौ और एक हजार के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, उस ऐलान से भारत में भारी उथल-पुथल मच गई थी। आम जनता को जिस तरह बैंकों के आगे लंबी-लंबी लाइनों में दिन-रात खड़े रहना पड़ा था, और अपने ही कमाए पैसे हाथ से चले जाने की पीड़ा जनता ने सही थी, उसका कोई सटीक वर्णन कर ही नहीं सकता।

नोटबंदी से कितने घर बर्बाद हो गए, पटरी पर चल रहा जीवन एकदम से पथरीले रास्तों पर आ गया। तब मोदी जी ने देशवासियों से 50 दिन का वक्त मांगा था कि सब कुछ ठीक नहीं रहा तो जिस चौराहे पर बुलाओगे, आ जाऊंगा। हालाकि किसी प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, मगर राष्ट्रभक्ति में लोगों ने चौराहे वाली भाषा को भी स्वीकार कर लिया। 50 दिन तो लाइनों में ही गुजर गए और उसके बाद रोजगार चले जाने, व्यापार ठप हो जाने, जमा-पूंजी के रद्दी हो जाने के गम से उबरने की प्रक्रिया अभी चल ही रही है कि सात साल बाद नोटबंदी का एक और बम सरकार ने फोड़ा है। इस बार पर्दे पर मोदी जी नहीं आए, वे विदेश यात्रा पर थे। उनकी जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया है कि अब 2 हजार के नोट भी बैंकों में वापस जमा करने होंगे, वो भी 30 सितंबर तक। इसके बाद इन नोटों का क्या होगा, पता नहीं ?

गौरतलब है कि भारत में 2016 नवंबर से पहले बड़े नोटों में 5 सौ और हजार के नोट प्रचलन में थे। मोदी जी ने हजार के नोट तो पूरी तरह बंद कर दिए और पांच सौ के नोट की शक्ल बदल दी। हजार के बदले 2 हजार के नोट आए और नए पांच सौ के नोट के साथ 2 सौ का नोट भी लाया गया। मोदी जी ने कालेधन के खात्मे के लिए नोटबंदी को जरूरी बताया था। उनके प्रवक्ताओं ने आतंकवाद, नशीली दवाओं, नक्सलवाद आदि पर रोकथाम के लिए और देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नोटबंदी को सही ठहराया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जिन नोटों को अमान्य करार दिया गया था, उनका 99 प्रतिशत से अधिक यानी करीब पूरा पैसा बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया था। 15.41 लाख करोड़ रूपए के जो नोट अमान्य हो गए, उनमें से 15.31 लाख करोड़ रूपए के नोट वापस आ गए थे। तो फिर किस काले धन को पकड़ने की तरकीब नोटबंदी से निकाली गई थी, यह अब तक समझ से परे है। नोटबंदी की कवायद के बाद से कितना कालाधन बरामद हुआ, इस पर अब तक कोई आंकड़ा सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है हालाकि, फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद को बताया था कि नोटबंदी सहित विभिन्न काला धन विरोधी उपायों के माध्यम से 1.3 लाख करोड़ रूपए के कालेधन की वसूली की गई है।

नोटबंदी का एक उद्देश्य नकली नोटों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाना भी बताया गया था लेकिन हकीकत ये है कि 2016 के बाद नकली नोटों की बरामदगी बढ़ गई। पिछले साल आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में जाली नोटों में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिसमें 500 रूपए के नकली नोटों में 101.93 प्रतिशत और 2000 रूपए के नकली नोटों में 54 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि नोटबंदी के उद्देश्य पर नकली नोटों का पानी फिर चुका है।

हजार के बदले 2 हजार के नोट लाने का क्या औचित्य, यह सवाल भी तब खूब उठा था क्योंकि बड़े नोट के तौर पर अधिक धन जमा करने में आसानी ही होगी। तब तर्क दिया गया था कि पांच सौ और हजार के नोट खत्म हो जाने की भरपाई के लिए 2 हजार के नोट चलाए जा रहे हैं। तब भी आम आदमी के नजरिए से विचार नहीं किया गया था कि रोज कमाने-खाने वाले लोगों के पास 2 हजार का नोट कैसे आएगा और अगर आ भी गया तो वह उसे किस तरह बाजार में तुड़ा पाएगा। अगर कभी नोट गिर जाए या चोरी हो जाए तो एक साथ 2 हजार का नुकसान होगा, जो गरीबों के लिए बहुत बड़ा है। जो गृहणियां रोज की सब्जी या अनाज खरीदने में थोड़ी बहुत बचत कर लेती हैं, उनके लिए भी 2 हजार के नोट का इस्तेमाल व्यावहारिक तौर पर कठिन था। इतनी बड़ी रकम के नोट की उपयोगिता केवल धनाढ्य तबके के लिए थी, जो एक साथ हजारों खर्च करने का माद्दा रखते हैं। आज की तारीख में ऐसे ही लोगों के पास काले धन के तौर पर 2 हजार के नोटों के बंडल होंगे। अब सरकार ने इसे भी बंद करने का ऐलान किया है, तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब फिर से एक हजार के नोट लाए जाएंगे या 2 हजार के नोट किसी नई शक्ल-सूरत में आएंगे और अगले चार महीनों में बैंकों के पास 2 हजार के नोट जमा करने से आखिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को गलत काम करने होते हैं, वे कोई न कोई तरीका तलाश ही लेते हैं और ईमानदार लोग ऐसी कवायद में पिस जाते हैं।

अभी आरबीआई के नियमों के मुताबिक एक बार में 20 हजार तक के 2 हजार के नोट जमा किए जा सकते हैं और इसके लिए किसी पहचान प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। मतलब कोई रईस अपने सौ कारिंदों को अलग-अलग 20 हजार के नोट बदलने के लिए बैंकों में भेज दे, तो पता नहीं चल पाएगा कि आखिर यह संपत्ति किसकी है। यह तो काले धन को सफेद करने का सुनहरा मौका नोटबंदी की शक्ल मे सरकार ने दौलतमंद लोगों के सामने पेश किया है। गरीब आदमी ने किसी तरह जोड़-जाड़ कर दो चार नोट भी इकट्ठे किए होंगे, तो वो अब इस पूंजी को बैंक में बदलने के लिए परेशान होगा।

आम आदमी के लिए कोरोना के बाद से परेशानियां और बढ़ गई हैं, जिनसे बेपरवाह मोदी सरकार ने एक और चाबुक जनता की पीठ पर मारा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद भी दो हजार रूपए का नोट लीगल टेंडर यानी वैध रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर अभी उसे बदलने का फैसला क्यों लिया गया। आखिर सरकार की मंशा क्या है ? उसके इरादों पर इतनी धुंध क्यों छाई हुई है ? सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए कि 30 सितंबर के बाद दो हजार के नोटों का वो क्या करेगी। सरकार की नीयत में यह अस्पष्टता देशहित में नहीं है।

बेसब्र न हो मुस्लिम समाज

सुलगने न दें नफरत की आग

महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की घटनाओं में यह भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय- जिसने हाल के ज्यादातर मामलों में बहुत समझदारी दिखाई, भड़काऊ बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उलटे हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में फूल बरसाकर, शरबत पिलाकर अपनी तरफ से सद्भाव जताने की कोशिश की, अब शायद अपना सब्र खोने लगा है। लेकिन अगर वह किसी तस्वीर को मुद्दा बनाने की कोशिश करके, किसी फिल्म का जवाब आपत्तिजनक पोस्टरों से देकर या अपने समाज की लड़की के गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती पर ऐतराज करके अपनी बेचैनी का इजहार कर रहा है तो कहना होगा कि ये तरीके कतई ठीक नहीं हैं।

पिछले साल रामनवमीं और हनुमान जयंती पर देश के अलग-अलग हिस्सों को साम्प्रदायिकता की आग में झुलसते हम सबने देखा था। अभी मई के महीने में फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे मालूम होता है कि दो समुदायों के बीच नफरत की चिंगारी कभी भी, कैसे भी भड़काई जा सकती है।

तेलंगाना के मेडक जिले के नरसापुर में एक रेस्तरां मालिक और गैस सिलेंडर की डिलीवरी देने वाले शख्स के बीच हुई हल्की सी हाथापाई देखते ही देखते एक मजहबी वारदात में बदल गई। रेस्तरां मालिक था मोईनुद्दीन और डिलीवरी बॉय लिंगम, और ये नाम तिल का ताड़ बनाने के लिए काफी थे। स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष मुरली यादव और पार्षद राजेंद्र-जिनका संबंध भाजपा से बताया जाता है, की अगुवाई में भीड़ ने मोईनुद्दीन की जमकर पिटाई कर दी। अपनी मां के साथ बीच-बचाव करने आई मोईनुद्दीन की गर्भवती बहन को भी भीड़ ने नहीं बख्शा और उसका गर्भपात हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद और बाकी बलवाइयों के खिलाफ तो पुलिस ने कोई कार्रवई नहीं की लेकिन मोईनुद्दीन को जरूर जेल भेज दिया।

दूसरी घटना महाराष्ट्र में औरंगाबाद के सिल्लोद में हुई, जहां सागर विट्ठल वानखेड़े नामक एक शख्स को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल पिक्चर में ऐसी तस्वीर लगाई थी जिसमें औरंगजेब जमीन पर पड़ा और शिवाजी का एक पैर उसके ऊपर है। अमीर शौकत शाह नाम के एक शख्स ने मुसलमानों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए सागर के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो शिंदे गुट के शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने दखल दिया और पुलिस को अंततः सागर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी हालाकि, बाद में सागर को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया।

तीसरी घटना मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में घटी। यहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे भावेश सुनहरे को मुस्लिम महिला मित्र के साथ घूमते देख मुसलमान युवकों ने घेर लिया और उसके साथ मारपीट की, उसकी मित्र को भी इस्लाम को लेकर भाषण पिलाया गया। जो लोग बीच बचाव करने आए, उन्हें चाकुओं के वार झेलने पड़े। इससे कुछ ही दिन पहले इसी शहर के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में 'द केरला स्टोरी' फिल्म के विरोध में या कहें कि उसके जवाब में बेनामी पोस्टर लगाए गए थे जिनमें मुस्लिम लड़कियों से भगवा लव ट्रैप में न फंसने की अपील की गई थी और हिंदू संगठनों से सावधान रहने को भी कहा गया था। गनीमत है कि दोनों मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया है।

इन सभी घटनाओं में एक बात साफ है कि इनमें बेवजह बात का बतंगड़ बनाया गया। मेडक में जिस मामूली से विवाद को समझा बुझाकर शांत करवाया जा सकता था, उसे जान बूझकर भड़काने और उसकी आंच पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। सिल्लोद का प्रसंग तो हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक भी। आखिर आज के मुसलमानों को औरंगजेब से क्या लेना-देना है जो एक तस्वीर से उनकी भावनाएं आहत हुई जा रही हैं, और ऐसे मामले में विधायक महोदय की दखलंदाजी समझ से परे हैं, खास तौर से तब जब वे अपनी पार्टी की विचारधारा को अच्छी तरह जानते-समझते हैं। वे भलीभांति जानते होंगे कि उनकी पार्टी और सरकार उनके ऐसे क्रियाकलाप से कभी सहमत नहीं होगी।

महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की घटनाओं में यह भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय- जिसने हाल के ज्यादातर मामलों में बहुत समझदारी दिखाई, भड़काऊ बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, उलटे हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में फूल बरसाकर, शरबत पिलाकर अपनी तरफ से सद्भाव जताने की कोशिश की, अब शायद अपना सब्र खोने लगा है। लेकिन अगर वह किसी तस्वीर को मुद्दा बनाने की कोशिश करके, किसी फिल्म का जवाब आपत्तिजनक पोस्टरों से देकर या अपने समाज की लड़की के गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती पर ऐतराज करके अपनी बेचैनी का इजहार कर रहा है तो कहना होगा कि ये तरीके कतई ठीक नहीं हैं। नफरत का जवाब नफरत से देना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।

नए चेहरों के सहारे पार होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी की नैया ?

-अजीत कुमार शर्मा

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा हर तरह के दांव खेलने के लिए तैयार दिख रही हैं। पार्टी यह मान कर चल रही है कि 2023 में नए चेहरों के सहारे ही बीजेपी की नैया पार हो सकती है। सूबे में पार्टी की नैया को पार लगाने की कवायद आज से नहीं बल्कि वर्ष 2018 में कांग्रेस से मिली शिकस्त के बाद ही शुरू हो चुकी है। पार्टी हाईकमान अपने स्तर पर सर्वे भी कर चुकी है। इसलिए पार्टी हाईकमान ने राजस्थान के सीनियर और 70 साल के अनुभवी नेता ओम माथुर को बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस काम की जिम्मेदारी मिलते ही वो प्रदेश की जमीनी हकीकत और पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा करने में लगे हैं। इसके लिए वे प्रदेश के पांचों राजनीति गलियारे (पांचों संभाग) में सक्रिय हैं। इन राजनीतिक गलियारों में वो लगातार दौरा कर रहे हैं। फीड बैक के आधार पर यह तय माना जा रहा हैं कि पार्टी आधे से ज्यादा पुराने चेहरों को ड्रॉप करने का मन बना चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर के लिए नए चेहरे तलाशे जा रहे हैं भले ही वो आयातित ही क्यों न हों ?

छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के गलियारों में जनता की नब्ज टटोलने में सूबे के प्रभारी लगे हैं। विशेषकर बस्तर की नब्ज को पकड़कर उसका इलाज करने की कवायद में जुटे हैं। क्योंकि प्रदेश में सत्ता की चाबी यही से खुलती है। यही से चौथी बार सत्ता का स्वाद चखा जा सकता है। यही वजह है कि वो लगातार बस्तर प्रवास पर रह रहे हैं। हाल ही में बस्तर संभाग के जगलपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में दौरा कर विधानसभा कोर कमेटी की बैठक ले चुके हैं। वे पार्टी के सीनियर और जूनियर नेताओं से बातचीत करने के अलावा नए चेहरों से मिलने से भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के प्रभारी रह चुके 70 वर्षीय ओम माथुर सबके अनुभवों को समेटने में लगे हैं।

सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 50-50 का आंकड़ा रह सकता है। यानी पार्टी 50 फीसदी सीटों पर नए चेहरों और 50 फीसदी सीटों पर पुराने चेहरों को मौका दे सकती है। इनमें नए चेहरों पर बड़ी संख्या में दांव लगाया जा सकता है। पार्टी में कई नेता 60, 70 और 80 साल के हैं। कुछ को अनौपचारिक रूप से रिटायर भी किया जा सकता है। वहीं कई पुराने चेहरों को मैनेज करने के लिए लोकसभा में भी भेजा जा सकता है।

हो सकते हैं विपरीत प्रभाव

यहाँ यह बताना लाज़मी होगा कि इसका कई विधानसभा क्षेत्रों में विपरीत प्रभाव भी पड़ता दिख रहा हैं। मसलन जो पुराने और जीवट कार्यकर्ता हैं उनमें नए प्रत्याशी के चयन को लेकर कोई मापदंड नहीं अपनाये जाने की बात सुनकर कहीं न कहीं नाराजगी झलकने लगी हैं। मसलन नव प्रवेशित लोगों को लेकर उनके इलाके में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। वहीँ कुछ वर्तमान भाजपा विधायकों ने तो खुलकर अपना विरोध भी दर्ज कराया हैं। बहरहाल मामला ज्यादा तूल न पकडे, इसे लेकर भाजपा सतर्कता भी बरत रही हैं।

साल 2018 में मिली हार में पुराने चेहरों के बीच गुटबाजी, खींचतान और नाराजगी सामने आई थी। वहीं एंटी इनकंबेंसी की बयार ने भी खेल बिगाड़ा था। इस बार पार्टी इन्हीं खाइयों को पाटने की प्रक्रिया में लगी है। इसलिए नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। दूसरी ओर पार्टी हाईकमान ने प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव को खुलकर काम करने की इजाजत दे रखी है। उन्हें प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आगे रहकर कार्य करने के लिए और बोलने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।

गुरुवार को बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर रायपुर में 309 से ज्यादा लोगों का प्रवेश भी इसी का हिस्सा हो सकता है। पार्टी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की रीति.नीति से प्रभावित होकर 309 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। इसमें छत्तीसगढ़ की जानी-मानी हस्तियां शामिल रहीं। इनमें दो बड़े नाम पद्मश्री अनुज शर्मा और राधे श्याम बारले शामिल हैं। वहीं पूर्व आईएएस राजपाल सिंह त्यागी और राज्य अलंकरण से सम्मानित प्रदेश के 13 कलाकार, समाज प्रमुख, जन प्रतिनिधि, किसान, छात्र, अधिवक्ता, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, व्यापार जगत की मशहूर हस्तियां, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार शामिल हैं।

चर्चा है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के रहने वाले पद्मश्री अनुज शर्मा को भाटापारा से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है क्योंकि उनके 2008 से ही बीजेपी में आने की कवायद चल रही थी। भाटापारा-बलौदाबाजार को लेकर उन्हें आश्वासन मिल चुका है। फि लहाल, भाटापारा से शिवरतन शर्मा विधायक हैं। वहीं कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व आईएएस राजपाल सिंह त्यागी को भी टिकट मिल सकता है। युवा नेताओं की लिस्ट में पहले से ही पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, भिलाई के दया सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। सियासी गलियारे में इस बात की भी संभावना है कि भविष्य में कई युवा नेता, आईएएस, आईपीएस, वीआरएस लेकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के भी कई युवा नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, छत्तीसगढ़ बीजेपी इन नए चेहरों के सहारे अपनी नैया पार लगा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

पुरानी संसद अब विपक्ष को सौंप देना चाहिए !

श्रवण गर्ग

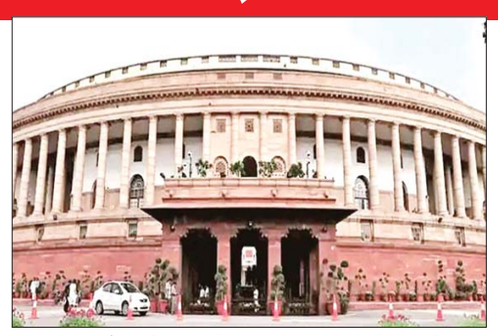

रविवार, 28 मई 'सावरकर जयंती' के दिन नई संसद के उद्घाटन अवसर पर पवित्र 'सेंगोल' के साथ-साथ नरेंद्र मोदी ने अपने आपको भी देश के संसदीय इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए स्थापित कर लिया ! आगे आने वाले सालों में मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हरेक नई हुकूमत स्पीकर की कुर्सी के निकट स्थापित किए गये राजदंड की चमक में मोदी-युग के प्रताप और ताप को महसूस करती रहेगी।

राजनीतिक सत्ता के महत्वाकांक्षी प्रत्येक राजनेता के अंतर्मन में यह संशय बना रहता है कि अप्रतिम नायकों का जब भी उल्लेख होगा, इतिहास उसे किस स्थान पर रखना चाहेगा ? जिन नायकों के मन में स्थान को लेकर शंका ज़्यादा बनी रहती है, वे अपने कार्यकाल के दौरान ही इतिहास में अपनी जगह घोषित कर देते हैं। एक ऐसी जगह जिसके साथ वर्तमान की तरह भविष्य में छेड़छाड़ नहीं की जा सके।

नई संसद के उद्घाटन मौक़े पर दोनों सदनों की सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता यानी राष्ट्रपति की भूमिका केवल एक शुभकामना संदेश प्रेषित करने तक सीमित थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस ऐतिहासिक प्रसंग पर उपस्थित थे पर उनकी सुप्रीम कमांडर वहाँ नहीं थीं। राज्यसभा के सांसद थे, उपसभापति थे पर उनके सभापति नहीं थे। वे पूर्व राष्ट्रपति ज़रूर मौजूद थे जिनका शिलान्यास समारोह के समय स्मरण नहीं किया गया था, पर उनके साथी रहे उपराष्ट्रपति अनुपस्थित थे।

देश के संसदीय इतिहास का इसे अभूतपूर्व क्षण माना जाना चाहिए कि दोनों सदनों में करोड़ों देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 260 सांसद विरोध स्वरूप अनुपस्थित थे। उनका बहिष्कार इस बात को लेकर था कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं ? यह अधिकार तो राष्ट्रपति का है। एनसीपी सांसद और वरिष्ठ राजनेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बाद में दुख जताते हुए कहा कि समारोह का निमंत्रण पत्र उन्हें सिर्फ़ तीन दिन पहले ही व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था।

अपने पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने न सिर्फ़ इक्कीस विपक्षी दलों के सांसदों के प्रतिष्ठापूर्ण समारोह में अनुपस्थिति का एक बार भी ज़िक्र नहीं किया, मोदी जब महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, बाहर सड़कों पर पुलिस महिला पहलवानों पर टूटी पड़ रही थी और नई संसद के भीतर बैठे आरोपित सांसद अपने नेता के दावों को सुन मेज़ थपथपा रहे थे।

सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों को अगर अपने ही द्वारा चुनी गई आदिवासी महिला राष्ट्रपति, विपक्षी दलों और राष्ट्र के गौरव की प्रतीक महिला एथलिस्ट्स के सम्मान की ज़रा सी भी परवाह नहीं बची है तो चिंता के साथ सवाल किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मुल्क को किस दिशा और दशा में देखना चाहते हैं ! इस हक़ीक़त को किसी अज्ञात भय के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए कि नई संसद में बैठने के स्थान तो बढ़ गए हैं, पर सत्ता पक्ष सरकार का सारा कामकाज बग़ैर विपक्ष के भी निपटाने को तैयार है !

इस तरह के निर्णय के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नज़र नहीं आता कि 'सेंट्रल विस्टा' के तहत प्रारंभ की गईं दूसरी सभी परियोजनाओं को अधूरे में छोड़कर नई संसद पहले तैयार करने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को ज़मीन पर उतारने के काम में दस हज़ार मज़दूरों को झोंक दिया गया ! नई संसद का उद्घाटन, नई लोकसभा के गठन के साथ साल भर बाद भी हो सकता था। कोई तो गूढ़ कारण रहा होगा, जिसके चलते नई संसद के उद्घाटन के लिए दस महीनों के बाद ही होने वाले चुनावों तक प्रतीक्षा करना ज़रूरी नहीं समझा गया !

देश को जानकारी है कि 27 अगस्त 2015 को घोषित प्रधानमंत्री की सौ शहरों को 'स्मार्ट सिटीज़' में विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ आठ साल के बाद भी आधी-अधूरी हालत में पड़ी अपने 'उद्धार' की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन परियोजनाओं के भविष्य की अब केवल कल्पना ही की जा सकती है!

हिंदू राष्ट्र के स्वप्नदृष्टा सावरकर की जयंती पर मंत्रोच्चारों के बीच सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक 'सेंगोल' की प्राण-प्रतिष्ठा संविधानसम्मत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर अब और ज़्यादा संदेह उत्पन्न करती है। डर यह भी लगता है कि जिस हुकूमत को आज राष्ट्रपति और विपक्ष की अनुपस्थिति नहीं खलती उसे आने वाले दिनों में संविधान और लोकतंत्र की उपस्थिति भी ग़ैर-ज़रूरी लग सकती है।

प्रधानमंत्री ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच अपने सपनों की नई संसद में प्रवेश कर लिया है ! अपनी 'जनता' को तो उन्होंने 2014 में ही चुन लिया था ! सुप्रिया सुले का कहना है कि- 'हम सब पुरानी संसद से प्यार करते हैं। वह भारत की आज़ादी का वास्तविक इतिहास है।' प्रधानमंत्री अगर उचित समझें तो पुरानी संसद और पुराने इतिहास की हिफ़ाज़त का काम विपक्ष को सौंप कर और ज़्यादा निश्चिंत हो सकते हैं !'

बेरोजगारों को भत्ता नहीं, रोजगार दीजिए

मधुरेंद्र सिन्हा

कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की किताब के कुछ पन्ने इस्तेमाल किए, मसलन मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त ट्रांसपोर्ट वगैरह। कांग्रेस उससे आगे बढ़कर बेरोजगारी भत्ता भी लेकर आई। अब तक आर्थिक विशेषज्ञ मुफ्त की बिजली और पानी पर सवाल उठा ही रहे थे कि कांग्रेस ने अपने तरकश से बेरोजगारी भत्ता का नया दांव खेल दिया। पाठकों को याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और उसकी आलोचना भी हुई थी। दरअसल नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने यह सुझाव दिया था कि हर बेरोजगार को कम से कम 2,500 रुपये भत्ता मिलना चाहिए।

लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने यह फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में चलाया और यह लोकप्रिय हो गया। पर कांग्रेस ने अभिजीत बनर्जी के सुझाव का वह हिस्सा गायब कर दिया, जिसमें उन्होंने राजस्व अनुशासन की बात कही। उन्होंने नए टैक्स लगाने की भी बात कही और कुछ टैक्स बढ़ाने की भी बात की थी। लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुफ्त की बिजली-भत्ता वगैरह को मिलाकर राज्य के कोष पर लगभग 54,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। 5.4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज से दबे कर्नाटक को अब यह भार भी सहना पड़ेगा। इस कर्ज के ब्याज को चुकाने पर इस साल राज्य को लगभग 35,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यह सारा पैसा कहां से आएगा, इस बारे में सरकार खामोश है।

कर्नाटक में अन्य राज्यों की तुलना में बेरोजगारी कम है । फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां मार्च, 2023 में बेरोजगारी दर 2.7 फीसदी थी, जो देश के औसत 4.2 फीसदी से कम है। फिर भी यह संख्या बहुत है। इससे अच्छा है कि रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रमों पर जोर दिया जाए। समस्या यह है कि सातवें वेतन आयोग ने देश में सरकारी नौकरियां सृजित करने पर कुठाराघात किया है। सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य के वेतन इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन सरकारों के बजट पर भारी बोझ आ गया है, जिन्होंने इसे मंजूर कर लिया है।

कर्नाटक में इस साल के अंत तक सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने इसे राज्य में लागू करने के लिए आयोग की समिति को 16 नवंबर तक की अवधि दी है। कर्नाटक में इसे लागू करने के बाद सरकार के खर्च में 12 से 18,000 करोड़ रुपये का इजाफा हो जाएगा। वहां के ढाई लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए यह शानदार तोहफा होगा, पर वे इससे ही खुश नहीं हैं। पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। यह पेंशन व्यवस्था अवकाश प्राप्त लाखों सरकारी कर्मचारियों को मलाई खिलाने जैसी है, जिसमें बड़े अफसरों को प्रति व्यक्ति लाखों रुपये महीना तक मिल सकता है। जाहिर है, ऐसी बढ़िया स्थिति हर कोई चाहेगा। कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों के इस लालच का फायदा हिमाचल प्रदेश में भी खूब उठाया है। कर्नाटक में सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो जाने के बाद जाहिर है कि सरकारी पदों पर नियुक्तियां प्रभावित हो जाएंगी। वहां के कर्मचारी यूनियन का कहना है कि राज्य में 39 फीसदी पद यानी लगभग दो लाख से भी ज्यादा पद रिक्त हैं, जिस कारण अन्य कर्मचारियों पर दबाव पड़ रहा है। अभी वहां पांच लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। अब राज्य के सामने समस्या होगी कि वह वेतन आयोग की सिफारिशें माने या फिर नए कर्मचारियों की नियुक्ति करे। जाहिर है कि वह ऐसे में बड़े पैमाने पर बहाली नहीं करना चाहेगी, बल्कि राज्य में बेरोजगारी भत्ता देते रहना चाहेगी।

ऐसा नहीं है कि यह हालत सिर्फ कर्नाटक की है। दिल्ली में सरकार मुफ्त बिजली-पानी दे रही है, लेकिन रोजगार नहीं। हजारों अस्थायी कर्मचारी वर्षों से आधी तनख्वाह में लटके पड़े हैं।

तम्बाखू निषेध दिवस

विश्व तम्बाखू निषेध के अवसर पर जेसीआई मेडिको सिटी द्वारा मरीन ड्राइव तेलीबांधा रायपुर में जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। शहर के कई प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने लोगों को तम्बाखू,गुटखा,गुड़ाखु सिगरेट आदि व्यसनों के दुष्परिणामों को समझाया। विभिन्न प्रकार के सजीव चित्रण भी किये गए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग कालेज के स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक द्वारा बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया।

मैट्स यूनिवर्सिटी और पाजीटिव हेल्थ जोन के बीच एमओयू

रायपुर। छात्तीसगढ़ के निजी विश्विद्यालयों में अपनी विशिष्ट स्थान रखने वाले मैट्स यूनिवर्सिटी के साथ पाजीटिव हेल्थ जोन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। डॉ अनिल गुप्ता डायरेक्टर श्रीगणेश विनायक आई हास्पिटल एंड पाजीटिव हेल्थ जोन और डॉ नरेन्द्र पाण्डेय चीफ एक्जीक्यूटिव लाइफ कैम्पस शामिल हुए।

शिक्षा और ज्ञान का अर्जन करना मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक है।शिक्षा दो प्रकार की होती है।कौशल और मूल्यपरख शिक्षा। आज स्कूल, कॉलेज हमें कौशल और दक्षता सिखलाने में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे है जो हमे धनोर्पार्जन हेतु व्याव्यसायिक दक्षता एवँ कैरियर से सम्बंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे है।लेकिन वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम हमे जीवन मूल्यों के कई पहलुओं जैसे तनाव प्रबन्धन, जीवन प्रबन्धन,मन प्रबन्धन एवँ विभिन्न सामाजिक और व्यवहारिक प्रबन्धन को सीखा पाने में असमर्थ है।

तनाव, चिंता,अवसाद और बीमारियों से भरी वर्तमान दुनियाँ में आवश्यकता है, सन्तुलित जीवन जीने की।भौतिकतावाद और आध्यत्मवाद के मध्य सन्तुलन स्थापित करने की एवँ स्वास्थ्य और धन के बीच संतुलन पैदा करने की।धनोर्पार्जन एवँ भौतिक सुखों के लिए स्कूल और कॉलेजो की भौतिकतावादी शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म,शांति और जीवन संतुलन के लिए व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है जो जीवनपर्यंत चलने वाली होती है।

जीवन के लिए जीवन भर सीखने के लिए लाइफ कैम्पस व्यवहारिक एवँ वास्तविक जीवन मे सफल विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के अनुभवों द्वारा आपकी व्यवहारिक अन्तर्दृष्टि की जिज्ञासा को पूर्ण करने का प्रयास करता है। वास्तविक एवँ व्यवहारिक ज्ञान के लिए लाइफ कैम्पस आनलाईन/आफलाईन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराता है।जहाँ वास्तविक जीवन के उदाहरणों से सुखी, स्वास्थ और पूर्ण जीवन का व्यवहारिक दृष्टिकोण सिखाया जाता है।

जीएसटी से राज्यों को राजस्व हानि, भरपाई की जल्द हो स्थायी व्यवस्था

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक में हुए शामिल

- केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की 2659 करोड़ की राशि जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया
- कोयला एवं अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन का किया आग्रह
- राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर रखी अपनी बात

रायपुर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिन्दुओं के अतिरिक्त राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। इस मौके पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे।

बैठक के एजेंडे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2047 का विकसित भारत, टीम इंडिया की भूमिका पर कहा देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई पर ज़ोर देते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की गयी है।

उन्होंने कहा एनएमडीसी द्वारा राज्य में स्थित इकाइयों को 25-30 प्रतिशत आयरन ओर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने समुचित आयरन ओर राज्य की इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

श्री बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ के एमएसएमई उद्योगों को एसईसीएल से विगत 2-3 वर्षों से राज्य की आवश्यकता अनुरूप कोल नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया आदिवासी अंचल बस्तर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विगत चार वर्षों में लगभग 9 हजार करोड़ रूपए पूंजी निवेश हेतु एमओयू किए गए हैं। इनमें से इस्पात उद्योगों के लिए प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन आयरन ओर की आवश्यकता होगी। उन्होंने अनुरोध किया कि इन इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप आयरन ओर आरक्षित रखा जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर की दर में भी 30 प्रतिशत छूट दी जाए।

इसके साथ ही उन्होंने 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने व समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध भी किया। बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ ही 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को हरित गतिविधियों के रूप में मान्य करते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन व्यपवर्तन से छूट प्रदान करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं व शिशुओं की देखभाल के सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75:25 करने का अनुरोध किया।

इसके अलावा उन्होंने बैठक में नवीन पेंशन योजना में जमा 19 हजार करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा भी उठाया। वहीं, उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के राजस्व हानि की भरपाई की कोई स्थायी व्यवस्था अतिशीघ्र की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कम प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 2659 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध कराने की मांग की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी की 4 हजार 170 करोड़ राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरण करने का आग्रह किया। वहीं, इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत सिविल सूट याचिका में केंद्र सरकार की ओर से जल्द जवाब प्रस्तुत कर निराकरण करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयला एवं अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन की मांग की।

उन्होंने कहा संशोधन नहीं होने से राज्य के वित्तीय हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11 हजार 828 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त करने का आग्रह भी किया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्रा.लि. जयराम काम्पलेक्स गली, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979